संयम ◆संस्कार ◆संतुलन

R.N.I. No.-UPHIN/2004/22466

वर्ष-23 अंक- 58
पृष्ठ 8
रविवार
15 नवम्बर 2026
प्रातः संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

शहर समता

प्रयागराज से प्रकाशित Email : shaharsamta@gmail.com Website : https://Shaharsamta.com

सम्पादक-उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध- वामिका गब्बी से कहा गया...

विचार- विदेशी पत्रकार के भारत आने पर...

खेल- सीरीज बराबर करने उतरेगा न्यूजीलैंड

मेरठ की पहचान माफियाराज और कट्टे से थी : योगी

कहा- वीरता पुरस्कार की राशि दोगुनी होगी, सैनिकों को 50 लाख तक के मकान पर स्टांप छूट



मेरठ (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचे हैं। वह शहर में दो घंटे 35 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कैंट स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक रैली में शामिल होकर सैनिकों के शौर्य, समर्पण और बलिदान को नमन करेंगे।

इसके अलावा वह स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल भी जाएंगे और शास्त्रीनगर में राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के आवास पहुंचकर उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

मेरठ में सैनिक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार की पहल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश देश की रक्षा तैयारियों में भागीदार बन रहा है।

सीएम योगी ने कहा, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अब लखनऊ में बन रही है। ऑपरेशन सिंदूर में इसी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश को केवल जवान ही नहीं दे रहा, बल्कि जवानों के हाथों में रहने वाले अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण भी प्रदेश में हो रहा है। स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ और कानपुर में बनाए जा रहे हैं, जबकि इसकी फाइनल असेंबलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कानपुर में स्किल एम्युनिशन का भी उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी-112 से लेकर सीमावर्ती जनपदों तक नए कमांड सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि राष्ट्रविरोधी ताकतों, स्लीपर सेल और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाया जा सके।

सीएम की रैली से पूर्व अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। सचिन सिरोही ने बताया कि उनका आज कोई कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के कथित विवादित बयान को लेकर जनसभा से पहले उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। उनका आरोप है कि पुलिस ने सुबह आठ बजे से उनके घर पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर रखा है। उन्होंने इसे लेकर नाराजगी भी जताई।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलिकॉप्टर सुबह 11रू50 बजे आरवीसी ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर उतरना था, हालांकि सीएम योगी का हेलीकॉप्टर कुछ देरी से हैलीपेड पर पहुंचा। यहां से वह कुलवंत सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे और पूर्व सैनिक रैली में शामिल होने के लिए सीएम रवाना हुए। कार्यक्रम के दौरान वह स्टेडियम स्थित बैडमिंटन हॉल भी जाएंगे।

इसके बाद मुख्यमंत्री आरवीसी ग्राउंड से हेलिकॉप्टर के जरिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग से शास्त्रीनगर स्थित राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के आवास जाएंगे। वहां उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री सीसीएसयू के हेलीपैड से अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे।

जयशंकर ने बताई नई विश्व व्यवस्था की तस्वीर

दुनिया अधिक अस्थिर होगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया और यूकरेन में जारी बड़े संघर्षों के बीच दुनिया की एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था बन रही है। इसें देशों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। अब फैसले लेने वाले स्वायत्त केंद्रों की संख्या भी बढ़ेगी। दुनिया का दृष्टिकोण भी पहले से ज्यादा लेन-देन पर आधारित होगा।



उन्होंने कहा, दुनिया इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसमें चीजें पहले से कहीं ज्यादा जटिल होंगी और भविष्य का अनुमान लगाना भी मुश्किल होगा। इसकी वजह है को सबसे ऊपर रखने वाले देशों की बढ़ती संख्या। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में संघर्ष, तनाव, अनिश्चितता और अस्थिरता देखने को मिल रही है। इनका असर देशों पर पड़ रहा है।

जयशंकर एक प्रमुख समाचार पत्र के समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, यही उस दौर की सोच और पहचान होगी, जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इसे अराजकता के रूप में देखें। लेकिन निश्चित रूप से देशों के बीच मुकाबला ज्यादा कड़ा होगा। देश अपने राष्ट्रीय हितों को ज्यादा मजबूती से सामने रखेंगे। इस लिहाज से दुनिया स्वाभाविक रूप से ज्यादा अस्थिर होगी।

उन्होंने कहा, नई विश्व व्यवस्था ज्यादा बहुध्रुवीय होगी। इसमें स्वतंत्र रूप से फैसले लेने वाले केंद्रों की संख्या भी काफी ज्यादा होगी। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर देश अपने विकल्पों और फैसलों में राष्ट्रीय हितों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। राष्ट्रीय हितों के कारण देशों के गठबंधन पहले की तरह मजबूत नहीं रहेंगे। वे ज्यादा लेन-देन पर आधारित होंगे। क्योंकि ये एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी गठबंधन कम मजबूत होंगे और उनमें लेन-देन का नजरिया ज्यादा होगा।

विदेश मंत्री ने कहा, भारत को इस नई स्थिति का सामना करने के लिए देश के भीतर अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये हमारी विदेश नीति की बुनियादी नींव हैं,क्योंकि इस दौर में आप देश की क्षमताओं को बहुत मजबूत किए बिना प्रभावी विदेश नीति नहीं अपना सकते। जयशंकर ने देश में औद्योगीकरण के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस दिशा में एक बहुत मजबूत नींव रखी गई है।

मेकेदातु बांध पर गठबंधन में रार, सीएम विजय से मणिकम टैगोर ने क्या की मांग? डीके शिवकुमार बोले

ये हमारा अधिकार

तमिलनाडु। कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस बयान पर कि मेकेदातु में बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता, तमिलनाडु कांग्रेस समिति (टीएनसीसी) के अध्यक्ष माणिकम टैगोर ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि बांध का निर्माण न केवल अवैध है, बल्कि इससे तमिलनाडु के किसानों की आजीविका पर भी गंभीर असर पड़ेगा। इस पर सीएम डीके शिवकुमार ने पलटवार करते



हुए कहा कि यह परियोजना कर्नाटक का अधिकार है। माणिकम टैगोर ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए शिवकुमार के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मैसूरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की थी कि मेकेदातु में बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता और केंद्र सरकार को इसके लिए अंतिम मंजूरी देनी चाहिए। टैगोर ने आरोप लगाया कि शिवकुमार का यह रुख सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का खुला उल्लंघन है।

महिला राइडर की बाइक पर बैठे राहुल गांधी, बोले

गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है भाजपा

हैदराबाद (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान वह एक गिग वर्कर की स्कूटी पर पीछे बैठकर रैली में पहुंचे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी बाइक रैली में शामिल हुए। हैदराबाद में आयोजित यह बाइक रैली शिल्पाकला वेदिका से शुरू हुई। राहुल गांधी ने नोवोटेल के पास गिग वर्कर्स को संबोधित किया। वह भारत समिट 2026 में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात हैदराबाद पहुंचे थे और नोवोटेल होटल में ठहरे हुए थे। हैदराबाद पहुंचने पर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, अन्य मंत्रियों और



कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया।

रैली में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले नोवोटेल होटल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हाई-प्रोफाइल सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत डॉग स्क्वॉड ने पूरे इलाके की जांच की। इसके साथ ही वाहनों की आवाजाही पर भी कड़ी नजर रखी गई।

हैदराबाद के हाइटेक सिटी स्थित जयभेरी ग्राउंड में राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम का शुभारंभ किया। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी मौजूद रहे। इस योजना का उद्देश्य गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाना है।

शिव प्रसाद चमोली को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार

राष्ट्रपति मुर्मु ने किया सम्मानित

मसूरी (एजेंसी)। उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि मसूरी के केम्पटी फॉल स्थित हिमालयन एडवेंचर इंस्टीट्यूट के संस्थापक-निदेशक शिव प्रसाद चमोली को देश के सर्वोच्च साहसिक सम्मान तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2024 (आजीवन उपलब्धि) से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित



समारोह में 84 वर्षीय चमोली को यह सम्मान प्रदान किया। पर्वतारोहण, स्कीइंग और रिवर राफ्टिंग के क्षेत्र में छह दशक से अधिक समय तक उनके उल्लेखनीय योगदान और साहसिक अभियानों में ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से प्रदान किया जाता है। इसमें कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति-पत्र और 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। इसे देश में साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। शिव प्रसाद चमोली का साहसिक जीवन अनेक ऐसी उपलब्धियों से भरा है, जिन्होंने भारतीय पर्वतारोहण और रिवर राफ्टिंग को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई।

PRESS
हमेशा आपके साथ
शहर समता NEWS

दैनिक एवं साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र

शहर समता
संयम ★ संसंकार ★ संतुलन

Website
www.shaharsamta.com

Subscribe on YouTube
youtube.com/@shaharsamtanews

सही खबर, सही समय पर

स्थापित 2001 • RNI Dainik UPHIN/2004/22466 • साप्ताहिक UPHIN/2001/03996 • कार्यालय 289/238 A कर्नलगंज प्रयागराज • संपर्क 9005239332, 9450482227

गुनाह छोटे–बड़े हो सकते हैं, लेकिन नेकी का कोई प्रकार नहीं: अब्दुल कुद्दूस

प्रयागराज। रजा जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमा की नमाज अदा की गई। मौलाना अब्दुल कुद्दूस ने अच्छे–बुरे कर्मों,



बच्चों की परवरिश और महिलाओं के अधिकारों पर प्रवचन दिया। नमाज के बाद देश–दुनिया में अमन–चौन के लिए दुआएं मांगी गईं। उन्होंने कहा कि गुनाह छोटे–बड़े हो सकते हैं, लेकिन नेकी का कोई प्रकार नहीं है। अकीदतमंदों को शीरनी भी बांटी गई। मौके पर हाजी अबरार अहमद, इलियास अहमद, रईस अहमद, नन्हें नूरी, गुलाम जीलानी, गुलाम यजदानी, गुलाम रसूल और खलील अहमद आदि रहे।

यूपीपीसीएल चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने दी एक महीने की मोहलत

प्रयागराज। बर्खास्तगी निरस्त होने के बाद भी कर्मचारी की विभागीय जांच पूरी नहीं हुई। हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पर यूपीपीसीएल चेयरमैन रणवीर प्रसाद के खिलाफ अवमानना का प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए नोटिस जारी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय जांच पूरी करने के आदेश का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के चेयरमैन रणवीर प्रसाद के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला माना है। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने प्रयागराज के चंद्रमोहन सिंघल की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची की बर्खास्तगी के आदेश को हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल 2025 को निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने विभाग को नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया था। इसमें विभागीय गवाहों की सूची और उनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाले प्रतिकूल साक्ष्यों की प्रतियां याची को उपलब्ध कराने, गवाहों को जांच में पेश करने और याची को उनसे जिरह का अवसर देने को कहा गया था।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि याची के सभी बकाया भुगतान और अन्य देयकों का निर्धारण जांच के परिणाम के बाद किया जाए। साथ ही याची के शीघ्र सेवानिवृत्त होने की संभावना को देखते हुए जांच जल्द पूरी करने को कहा था। आदेश की जानकारी दिए जाने के बावजूद विभाग ने इसका पालन नहीं किया।

हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड देखने के बाद आदेश की जानबूझकर अवहेलना का प्रथम दृष्टया मामला पाया। कोर्ट ने एक महीने में आदेश का पूरी तरह पालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं होने पर विपक्षी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं करने का कारण बताना होगा।

माघ मेले में पहली बार तीन हजार से अधिक बसें चलाने की तैयारी

प्रयागराज। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) ने माघ मेले के दौरान पहली बार तीन हजार से अधिक बसें चलाने की तैयारी की है। इस वर्ष माघ मेले में करीब 2500 बसों का इंतजाम किया गया था। वर्ष 2027 में ज्यादा भीड़ आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार बसों की संख्या बढ़ाकर 3100 करने पर मंथन चल रहा है। इनमें से 300 बसों को रिजर्व में रखा जाएगा, ताकि मुख्य स्नान पर्वों पर अचानक बढ़ने वाले यात्रियों के दबाव को नियंत्रित किया जा सके। प्रदेश के सभी रीजन से बसें मंगाई जाएंगी।

इस बार भी झूंसी और नैनी लेप्रोसी चौराहा क्षेत्र में अस्थायी बस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। स्नान पर्वों के दौरान झूंसी से गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर एवं पूर्वांचल के अन्य शहरों के लिए बसें उपलब्ध होंगी। नैनी लेप्रोसी से मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं रीवा रूट की बसें मिलेंगी। इसके अलावा, मुख्य स्नान पर्वों के दौरान भी विद्या वाहिनी अस्थायी बस स्टेशन से बसों का संचालन जारी रखने की योजना है। साथ ही, भारत स्काउट गाइड के पास भी एक नया अस्थायी बस स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है। यहां से लखनऊ, अयोध्या रूट की बस चलाने की योजना है।

माघ मेला–2026 के मुकाबले वर्ष 2027 में ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। इसी वजह से इस बार तीन हजार से ज्यादा बस संचालन की तैयारी की जा रही है। – रविंद्र कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन

कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

प्रयागराज। शुक्रवार को कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) न्यू डेमोक्रेसी के कार्यकर्ताओं ने बारा



तहसील में धरना दिया। उन्होंने एसडीएम अर्पित कुमार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेशकुमार को बर्खास्त करने, असंवैधानिक एसआईआर रद्द करने और मतदाता सूची चस्पा करने की मांग की गई। उपजिलाधिकारी ने ज्ञापन भेजने का आश्वासन दिया। धरने में कामरेड हीरालाल, राजकुमार पथिक, राम कैलाश कुशवाहा, विनोद सैलानी, भीमलाल, मकबूल शाह, राजेश आदिवासी,उमेश पटेल, पन्नालाल आदि रहे।

आखिर कहां लापता हैं प्रयागराज जोन के 214 मोस्ट वांटेड अपराधी, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

प्रयागराज। प्रयागराज जोन में 214 इनामी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। किसी पर 10 हजार तो किसी पर पांच लाख रुपये तक का इनाम घोषित है। प्रयागराज कमिश्नरेट में सर्वाधिक 90 और फतेहपुर में 62 अपराधी वांछित हैं। अब 50 हजार रुपये से अधिक के इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी का जिम्मा एसटीएफ ने अपने टारगेट में शामिल किया है।

संगीन अपराधों में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस व एसटीएफ लगातार अभियान चलाने का दावा कर रही है, लेकिन प्रयागराज जोन में 214 इनामी अपराधियों का खुलेआम घूमना पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

इनकी गिरफ्तारी के लिए 10 हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक के इनाम घोषित है। सवाल यह है कि जब इनके नाम, पते और आपराधिक इतिहास रिकॉर्ड में दर्ज हैं तो फिर इन तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं।

50 हजार रुपये से अधिक के करीब 41 इनामी बदमाशों पर एसटीएफ की विशेष नजर है। ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की भूमिका अहम मानी जा रही है। एडीजी कानून–व्यवस्था अमिताभ यश ने सभी जिलों से इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर अपडेट तलब किया है।



पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फतेहपुर में सबसे अधिक 62 शातिर अपराधियों पर इनाम घोषित है। ये कल्यानपुर, धाता, कोतवाली, असोथर, थरियांव, हथगांव, जाफरगंज, ललौली, मलवां और चांदपुर समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों के हैं।

थानों में दर्ज हैं ठिकाने, फिर भी बेखौफ घूम रहे बदमाश

इन पर 10 हजार, 25 हजार, 50 हजार और एक लाख रुपये तक का इनाम है। कौशाम्बी में 20 इनामी बदमाश पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। सैनी, कोखराज, मंझनपुर, करारी और पिपरी समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों के इन अपराधियों पर 10 हजार से 50 हजार रुपये तक का इनाम घोषित है।

प्रतापगढ़ में भी 23 बदमाश वांछित हैं। इनमें रानीगंज, संग्रामगढ़, कोतवाली, उदयपुर, कोतवाली देहात, कंधई और लीलापुर थाना क्षेत्रों के अपराधी शामिल हैं। इसके अलावा बांदा के दो, चित्रकूट के आठ और महोबा के सात बदमाशों पर भी इनाम घोषित है।

अपराधियों पर इनाम घोषित कर भूली पुलिस

प्रयागराज कमिश्नरेट में 90 इनामी अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। कोतवाली, सिविल लाइंस, कैंट, कीडगंज, कर्नलगंज, जार्जटाउन, दारागंज, धूमनगंज, झूंसी, नैनी, मेजा, मांडा, करेली, पूरामुफ्ती, एयरपोर्ट, सोरांव, नवाबगंज और घूरपुर समेत कई थाना क्षेत्रों के अपराधी इस सूची में शामिल हैं।

इसके अलावा बांदा के दो, चित्रकूट आठ, हमीरपुर दो, महोबा सात बदमाशों पर इनाम घोषित किया गया है। इनमें तीन पर पांच लाख रुपये तक के इनाम घोषित होने की बात भी सामने आई है। एसटीएफ के सीओ शैलेश सिंह का कहना है कि 50 हजार से ऊपर के इनामी बदमाश एसटीएफ के टारगेट पर हैं। काफी इनामी बदमाशों की एसटीएफ ने गिरफ्तारी किया है।

60 साल की उम्र भी नहीं बनी राहत का आधार, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

प्रयागराज। जमीन विवाद में हमले के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में 60 साल से अधिक उम्र के तीन दोषियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराध में केवल उम्र अधिक होने के आधार पर परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी की उम्र अधिक हो जाने मात्र से उसे परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रिहा करने का लाभ स्वतरू नहीं दिया जा सकता। परिवीक्षा पर रिहाई की मांग पर विचार करते समय आरोपी की उम्र के साथ उसके पूर्व आपराधिक इतिहास, सामाजिक परिस्थितियों और सुधार की संभावना को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अपराध की प्रकृति, हमले का तरीका और उसके परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं।

इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने गंभीर चोट व मारपीट के मामले में 60 साल से अधिक उम्र के तीन दोषियों को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए शेष सजा भुगतने का निर्देश दिया है। मामला फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र का वर्ष 1983 का है। जमीन पर निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। आरोपियों ने लाठी–डंडों और अन्य कठोर वस्तुओं से हमला किया था। इसमें भदौवा नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।



इसके खिलाफ बाबूलाल, घसीटवा उर्फ घसीटा, रामदास और रामलाल ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील लंबित रहने के दौरान घसीटवा की मृत्यु हो गई। अपीलार्थियों की ओर से दलील दी गई कि घटना के समय दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद था और उन्हें झूठा फंसाया गया है। साथ ही, जीवित अपीलार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। इसलिए उन्हें शेष सजा जेल में बिताने के बजाय परिवीक्षा पर रिहा करने का लाभ दिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने घटना की गंभीरता को देखते हुए परिवीक्षा का लाभ देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मौखिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया था। कम से कम आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी ठहराए जाने पर विचार करना चाहिए था। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए सजा बरकरार रखी।

13 साल बाद भी नहीं हो सकी परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति, सात नवंबर की समयसीमा बीती

प्रयागराज। 13 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे परिषदीय शिक्षकों को एक बार फिर झटका लगा है। सात नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश के बावजूद प्रदेश के जिलों में वरिष्ठता और पात्रता सूची तक तैयार नहीं हो सकी।

वर्षों बाद परिषदीय स्कूलों (कक्षा एक से आठवीं तक) के शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू तो हुई लेकिन अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को निर्देश दिए गए थे कि सात नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करनी है। बावजूद इसके प्रदेश के किसी भी जिले में पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं पूरी हो सकी। वरिष्ठता व पात्रता सूची भी अब तक तैयार नहीं हो सकी है। इससे शिक्षकों में नाराजगी भी दिखने लगी है।

प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति



तकरीबन 13 वर्षों से नहीं हुई। मामला कोर्ट तक पहुंचा। परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 16 अक्तूबर को पत्र जारी कर वरिष्ठता सूची व पदोन्नति तैयार करने के निर्देश दिए थे। स्थिति यह है कि कुछ गिने–चुने जिलों को छोड़कर बाकी किसी भी जिले के बीएसए ने यह विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।

पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य करने से भी नाराजगी

इस पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका विरोध कर रहे शिक्षकों का कहना है भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य करना ठीक है लेकिन पदोन्नति में यह गलत है। परिषद की ओर से बताया गया है कि प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले सहायक अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

जिन सहायक अध्यापकों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों का टीईटी उत्तीर्ण किया है, उन्हें प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति मिलेगी। उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी उत्तीर्ण सहायक अध्यापक और प्राथमिक स्तर का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन सकेगा। जिन अध्यापकों ने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, उनके पद सुरक्षित रखे जाएंगे। ऐसे शिक्षकों के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई स्पेशल टीईटी के परिणाम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सात नवंबर तक का समय दिया गया था लेकिन बीच में त्योहार आदि होने से वरिष्ठता सूची तैयार करने में देरी हुई है। जहां से विवरण नहीं आए हैं, उन्हें फिर से निर्देश दिए जा रहे हैं। –सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद

करंट की चपेट में आने से झुलसे किशोर की मौत

प्रयागराज। किरांव गांव में बृहस्पतिवार सुबह नीम की डाल काटते समय 17 वर्षीय लकी गौतम हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। उसे एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लकी बाबूलाल गौतम का पुत्र था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन घनी आबादी के बीच से गुजर रही है। बिजली विभाग से कई बार तार हटाने की मांग की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराने और धरना–प्रदर्शन की चेतावनी दी। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने घटना से अनभिज्ञता जाहिर की। क्षेत्रीय लेखपाल ने शनिवार को गांव पहुंचकर रिपोर्ट तहसील को देने की बात कही है।

राम नाम ही जीव को भवसागर से लगा सकता है पार : संत उर्मिला दास

प्रयागराज। बकसेड़ा के श्री रामजानकी मंदिर का प्रांगण इन दिनों राम नाम गुंजायमान हो रहा है। श्री सीताराम नाम



जप महायज्ञ के दूसरे दिन चित्रकूट धाम के संत उर्मिला दास ने कहा कि कलयुग के जीव को केवल राम नाम ही तृप्ति और मुक्ति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि गुरु बिना ज्ञान का दीप प्रज्वलित नहीं होता। बिना सद्गुरु के कोई भी प्राणी इस संसार रूपी महासागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही क्यों न हों। मौके पर डॉ. शिवकुमार केसरवानी, शारदा प्रसाद पांडेय, अनुपम त्रिपाठी, देवेश पांडेय उर्फ मुन्ना, राजनाथ पटेल, पवन कुमार यादव, उमाशंकर यादव, शिव बाबू साहू आदि रहे।

मुकदमे के आखिरी चरण में तथ्य जोड़ने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने भी नहीं दी राहत

प्रयागराज। मुकदमे की अंतिम बहस के दौरान लिखित बयान में नए तथ्य जोड़ने की कोशिश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि संशोधन में देरी का संतोषजनक कारण बताना जरूरी है। केवल बाद में जानकारी



मिलने का दावा पर्याप्त नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की अंतिम बहस के समय लिखित बयान में नए तथ्य जोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक देरी का संतोषजनक कारण न बताया जाए। केवल बाद में जानकारी मिलने का दावा करना पर्याप्त नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कानपुर नगर निवासी गोपी किशन खंडेलवाल की याचिका खारिज करते हुए दिया। याची ने लघुवाद न्यायालय के लिखित बयान में संशोधन की अर्जी खारिज करने को चुनौती दी थी। मामला मकान खाली कराने, बकाया किराया और क्षतिपूर्ति की वसूली से जुड़ा है। मकान मालकिन अर्चना त्रिपाठी ने वर्ष 2020 में मुकदमा दाखिल किया था। याची का कहना था कि विवादित संपत्ति का वर्ष 2019 में ही विभाजन हो चुका है।

कानपुर नगर निगम के प्रस्ताव के आधार पर कृष्णा त्रिपाठी के हिस्से को अलग मकान नंबर 92–ए आवंटित किया गया था। ऐसे में किरायेदारी भी विभाजित हो गई और अर्चना त्रिपाठी अकेले मुकदमा नहीं चला सकतीं। याची ने सितंबर 2025 में लिखित बयान में संशोधन की अर्जी दी थी। उनका दावा था कि संपत्ति के विभाजन की जानकारी अगस्त 2025 में मिली। कोर्ट ने कहा कि कथित विभाजन मुकदमा दाखिल होने से पहले का था। याची यह स्पष्ट नहीं कर सका कि उसने पहले इसकी जानकारी हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए थे।

कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन के लिए पूरी सतर्कता बरतने के बावजूद तथ्य पहले सामने नहीं लाया जा सका की शर्त पूरी करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत को मुकदमे का तीन महीने में निस्तारण करने का निर्देश दिया है।

34 साल पुराने मामले में सुपरवाइजर को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

प्रयागराज। पेपर मिल की मशीन में लोहे की पट्टी फंसाकर उत्पादन ठप करने के आरोप में बर्खास्त शिफ्ट सुपरवाइजर को 34 साल बाद भी राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू जांच को उचित मानते हुए बर्खास्तगी बरकरार रखी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन कर पूरी हुई जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने पेपर प्लांट की मशीन में लोहे की पट्टी डालकर उत्पादन ठप करने के आरोप में बर्खास्त शिफ्ट सुपरवाइजर को राहत देने से इन्कार कर दिया है।

कोर्ट ने बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। मामले के मुताबिक, मेरठ निवासी याची अनिल कुमार शर्मा मुजफ्फरनगर स्थित मेसर्स पसवारा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट सुपरवाइजर थे। 16 फरवरी 1992 को सुबह करीब पांच बजे ड्यूटी के दौरान प्लांट की मशीनें अचानक बंद हो गईं। जांच में मशीन के भीतर लोहे की पट्टी फंसी मिली। कंपनी ने मामले की घरेलू जांच कराई। आरोप साबित होने पर 28 मई 1992 को उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।

श्रम न्यायालय ने 10 सितंबर 2003 के अवार्ड में घरेलू जांच को निष्पक्ष और उचित माना था। इसे चुनौती देते हुए याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि गवाहों से जिरह का उचित अवसर नहीं दिया गया और जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई। दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करने पर भी आपत्ति जताई। कहा कि याची अब करीब 70 वर्ष के हैं, इसलिए बहाली संभव नहीं है और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने पाया कि याची ने आरोपपत्र का जवाब दिया और जांच में भाग लेकर गवाहों से जिरह भी की। गवाहों ने उन्हें मशीन के पास संदिग्ध गतिविधि करते देखने की पुष्टि की थी। कोर्ट ने कहा कि दूसरा नोटिस जारी करना अधिक उचित होता, लेकिन इसके अभाव में याची के प्रति कोई पूर्वाग्रह साबित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। ऐसे में श्रम न्यायालय के अवार्ड में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

सामाजिक कार्यकर्ता समाज शेखर को करारी में कौशाम्बी सांसद ने किया सम्मानित

प्रतापगढ़। कौशाम्बी के करारी इण्टर कॉलेज में कॉलेज व वसेरा संस्थान द्वारा बाल दिवस पर आयोजित ग्रामीण लोक गीत महोत्सव में प्रतापगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता समाज शेखर को



मुख्य अतिथि सांसद कौशाम्बी पुष्पेन्द्र सरोज द्वारा बाल मित्र सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। समाज शेखर को यह सम्मान समाज सेवा, बच्चों के हित में किए जा रहे कार्यों और लोक संस्कृति के संरक्षण में उनके योगदान के लिए दिया गया। सम्मान समारोह में उन्हें अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया।

इस अवसर पर आयोजित लोक उत्सव में बच्चों ने लोक गीत, लोक नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं, शिक्षक, अभिभावक व गणमान्य नागरिक सहित श्रृंगवेरपुर धाम के अध्यक्ष बाल कृष्ण पांडेय व पूर्व जिला सूचना अधिकारी जे एन यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सम्मान मिलने पर प्रतापगढ़ के बाबा भयहरणनाथ धाम की प्रबन्ध संस्थान तथा स्थानीय लोगों ने समाज शेखर को बधाई दी और इसे जिले के लिए गर्व का क्षण बताया।

लखनऊ में होगा कौशल दीक्षा समारोह, 21 नवंबर को आयेंगे पीएम

लखनऊ (संवाददाता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को लखनऊ आने वाले हैं। वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कौशल दीक्षा समारोह में देशभर के आईटीआई के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पड़ताल शुरू कर दिया है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से हर साल देशभर के आईटीआई के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ आयोजन अब तक दिल्ली के विज्ञान भवन में होता रहा है। पहली बार समारोह दिल्ली से बाहर लखनऊ में होने जा रहा है। 21 नवंबर को दोपहर बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम प्रस्तावित है।कौशल दीक्षा समारोह में देशभर के 40 ट्रेड और छह जोन के 64 टॉपर सम्मानित होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के छह विद्यार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न ट्रेड के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। समारोह में देशभर की आईटीआई से डेढ़ हजार विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

अयोध्या-काशी के बाद बीजेपी की मथुरा पर नजर

लखनऊ (संवाददाता)। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने मथुरा पर अपनी नजर गड़ा दी है। बीजेपी कान्हा की नगरी से सियासी संदेश देने को तैयार है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा को लेकर बीजेपी की रणनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 16 और 17 नवंबर को दो दिवसीय चिंतन बैठक करेगा। इसमें पार्टी के करीब तीन दर्जन से ज्यादा भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।17 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन की मजबूती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा संभव है। भाजपा अयोध्या में श्रीराम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम के बाद अब मथुरा को वैचारिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में रखने का संदेश देना चाहती है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा लंबे समय से भाजपा की राजनीति के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है। बता दें, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन–पूजन किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या और काशी की तर्ज पर मथुरा के विकास का संकेत दिया था। मुख्यमंत्री के बयान के बाद से ब्रज क्षेत्र में विकास और धार्मिक पर्यटन को लेकर सरकार की भावी योजनाओं पर चर्चा तेज हुई है। अब पार्टी के शीर्ष नेताओं की चिंतन बैठक को राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है। कृष्ण नगरी से भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से को साधने की जुगत लड़ा रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ क्षेत्रीय संगठन, जातीय समीकरण, किसान मुद्दे और चुनावी चुनौतियां बैठक के एजेंडे में रह सकती हैं। पार्टी नेतृत्व के लिए बैठक ब्रज क्षेत्र में संगठन की स्थिति का आकलन करने और चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने का अवसर भी होगी।भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 16 और 17 नवंबर को बैठक की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी पदाधिकारी चिंतन बैठक में शामिल होंगे।

हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं–अंगारा

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने नए सियासी मोर्चे का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा यानि एसपीएम रखा है। इस नये मोर्चे की बाबत प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई है।कोई इसे थर्ड फ्रंट बताकर इसके यूपी की सियासत में बड़ा दखल करार दे रहा है तो कोई इस गठबंधन को तरजीह ही न देने की बात कह रहा है।खैर कुछ भी नतीजे आये लेकिन सियासी पार्टियों को अपने–अपने समीकरण मजबूत रखने खातिर सक्रियता बढ़ाने के लिए मजबूर तो कर ही दिया है।इसी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी चिंतक एवं कायस्थ चित्रगुप्त महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव अंगारा ने तो एसपीएम को लेकर कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं।एसपीएम का भी हाल यही है। ये बोलते तो हैं कि बीजेपी को हुकूमत से हटाने और पिछड़ों, शोषितों, किसानों,नौजवानों के हक के लिए मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन सच बिल्कुल इतर है।

जरूरतमंद छात्राओं को सिलाई मशीन प्रदान कर प्रोत्साहित किया, कंबल एवं राशन भी वितरण किया गया

प्रयागराज। जुबैदा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कि तरफ से सामाजिक सरोकार और मानवता की मिसाल पेश करते हुए आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने अतिथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद एवं प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें उपहार भेंट किए गए।

इस अवसर पर एक ऐसी मेहनती और गरीब छात्रा, जो सिलाई के काम में बेहद कुशल है, उसे आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन भेंट की गई।

वहीं द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को कंबल



एवं राशन सामग्री का वितरण भी किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशुतोष शाही असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ रहे। इस अवसर पर चै के मैनेजर फरहान आलम ने जुबैदा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कि डेज़ी ज़ैदी को सम्मानित करते हुए मोमेंटो भेंट किया।कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता असरा नवाज़ भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करने के साथ–साथ बेटियों को शिक्षा, हुनर और आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करना रहा।इस आयोजन ने समाज में सेवा, सम्मान और महिला सशक्तीकरण का सकारात्मक संदेश दिया।

भाजपा को 50 सीटें भी मिल जाएं तो हैरानी होगी– अवधेश प्रसाद

लखनऊ (संवाददाता)। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर, केशव मौर्य के बयान, राहुल गांधी के फोन–टैपिंग के आरोपों और भाजपा के अखिलेश यादव की तुलना जिन्ना से करने पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव के चुनाव की लूट वाले बयान पर अवधेश प्रसाद ने कहा, हमारे नेता की ओर से कही गई बात पूरी तरह से सच है। उनके विचारों से मैं खुद को संबद्ध करते हुए कहता हूं कि भाजपा का यही चेहरा है और पिछले दिनों में देखा गया कि भाजपा वोट के अधिकार को खत्म करना चाहती है, जिसके लिए देश में लगातार संघर्ष चल रहा है। हमारे नेता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इसको बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही हैं। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद के बयान 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा, केशव प्रसाद की जमीन नहीं है, वे बुरी तरह से अपने क्षेत्र में चुनाव हार चुके हैं। पार्टी नेताओं की कृपा से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। पार्टी और सरकार में उनका सम्मान नहीं है। उनको ठीक से कुर्सी भी नहीं मिलती। राहुल गांधी के फोन–टैपिंग के आरोपों पर अवधेश प्रसाद ने कहा, ऐसा संभव है, भाजपा कुछ भी कर सकती है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा की ओर से अखिलेश यादव के जिन्ना कहने वाले बयान पर अवधेश प्रसाद ने कहा, अखिलेश यादव की



बढ़ती लोकप्रियता और जनता का उनके प्रति लगाव देखकर भाजपा घबरा गई है। जैसे–जैसे चुनाव करीब आता जाएगा, भाजपा इतना घबरा जाएगी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आने वाले दिनों में 2027 के चुनाव में भाजपा को अगर 50 सीटें भी मिल जाएं तो आश्चर्य की बात होगी। अखिलेश यादव जैसी लोकप्रियता देश में किसी और नेता की नहीं है। भाजपा की सरकार और नेताओं से प्रदेश के मतदाताओं का भरोसा समाप्त हो चुका है।

वकीलों का हंगामा, विधानसभा गेट पर धरना

बोले, मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन

लखनऊ (संवाददाता)। लखनऊ में शनिवार को अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर सैकड़ों वकील सड़क पर उतर आए।



कैसरबाग कोर्ट परिसर से विधानसभा तक निकाले गए पैदल मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं के बीच कई जगह धक्का–मुक्की हुई। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ते हुए वकील विधानसभा के गेट तक पहुंच गए और वहां धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। अधिवक्ताओं ने साफ कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। शनिवार सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में अधिवक्ता कैसरबाग स्थित कोर्ट परिसर में एकत्र हुए। यहां से उन्होंने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा की ओर पैदल मार्च शुरू किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग की थी। पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को समझाने और वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन वे आगे बढ़ने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने कैसरबाग से परिवर्तन चौक, हजरतगंज चौराहे और जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा के पास बैरिकेडिंग लगाकर अधिवक्ताओं को रोकने का प्रयास किया। वकीलों ने इन अवरोधों को हटाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों को रोकने और शांत कराने का प्रयास करते रहे लेकिन अधिवक्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार वे विधानसभा तक पहुंच गए और गेट पर धरना देकर मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट यानी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना है। वकीलों को अपने पेशेवर कार्य के दौरान मारपीट, धमकी, हमले और उत्पीड़न जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाया जाना जरूरी है। वकील कानून की रक्षा का काम करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच बनने से क्षेत्र के लोगों को न्याय हासिल करने में सुविधा होगी और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।अधिवक्ता आशुतोष ने कहा कि जब तक सरकार अधिवक्ताओं की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य वकीलों को उनके पेशेवर काम के दौरान होने वाली मारपीट, धमकी, हमले और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। इसी कानून को लागू कराने के लिए प्रदेशभर के अधिवक्ता आवाज उठा रहे हैं।

26,720 परिषदीय विद्यालयों में होगा सोशल ऑडिट

प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 20 प्रतिशत परिषदीय विद्यालयों का होगा सोशल ऑडिट

लखनऊ (संवाददाता)। योगी सरकार प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित परिषदीय विद्यालयों के 20 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए 26,720 परिषदीय विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने सोशल ऑडिट निदेशालय के निदेशक को एमओयू की हस्ताक्षरित प्रति भेजते हुए समझौते के अनुसार अग्रिम देय 50 प्रतिशत धनराशि के हस्तांतरण के लिए बैंक खाते का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिससे धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया समय से पूरी की जा सके। इस पहल से परिषदीय विद्यालयों में संचालित योजनाओं के वित्तीय और भौतिक पक्षों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सकेगा। सोशल ऑडिट से प्राप्त निष्कर्षों और सुधार संबंधी सुझावों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। एमओयू का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा योजना की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना है। इसके अंतर्गत योजना से संबंधित वित्तीय अभिलेखों, वाउचर, अनुदान वितरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। साथ ही योजना के भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन भी होगा। लाभार्थियों का फील्ड वेरिफिकेशन और सैंपल चेकिंग की जाएगी।

सोशल ऑडिट निदेशालय की टीम योजना के क्रियान्वयन में सामने आने वाली कमियों, वित्तीय अनियमितताओं और सुधार संबंधी सुझावों को शामिल करते हुए विस्तृत सोशल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

व्यंग्य की भाषा बोलें

(छप्पय)

अपनेपन का भाव मिलन का ताना–बाना।
तहज़ीबों को लाँघ गा रहे अपना गाना।
आडंबर की होड़ भूलते रिश्ते–नाते।
आगे रख मुस्कान पीठ पीछे गुर्राते।
हमदर्दी बेदम हुई सेल्फी का बाजार है।
मगर आधुनिक दौर पर दुनिया यह बलिहार है।।

अहंकार के भाव जुबाँ जब अपनी खोलें।
हास्य और परिहास व्यंग्य की भाषा बोलें।
धरती पर है पैर मगर तारों को चूमें।
भइया बहुत महान द्वार पर हाथी झूमें।
हवा हवाई तीर से चीरहरण कर मान को।
कुचल हँसी के प्राण को भरते हैं मुस्कान को।।

डॉ. प्रदीप चित्रांशी
लूकरगंज, प्रयागराज

विश्वनाथ में आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां अंतिम चरण पर

आज व्रतधारी खरना कर 36 घंटा निर्जला व्रत का किया शुभारंभ संध्याकालीन भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेगी व्रतधारी

विश्वनाथ, असम। आस्था का महापर्व छठ पूजा का तैयारी राज्यों के हिस्सों की तरह आज विश्वनाथ जिले के सभी छठ घाट में भी तैयारी अंतिम चरण पर है। इधर विश्वनाथ चारिआलि शहर के आमबाड़ी के केंद्रीय श्री श्री छठ घाट पूजा समिति के छठ घाट



भी प्रायः दुल्हन की तरह सज उठी है। समिति के अध्यक्ष बलवीर राय, सचिव नीरज सिंह, कोषाध्यक्ष क्रमशः विकास रौनियार, संदीप जयसवाल और प्रतिष्ठित व्यवसायी व समाजसेवी प्रभुनाथ सिंह, वरिष्ठ शिक्षक सूर्य नारायण पांडे आदि छठ घाट पहुंचकर घाट की तैयारी की जायज़ा लेने के साथ व्रतधारी की सभी प्रकार की प्रबंध किया गया है। इधर आज आस्था का महापर्व के दूसरे दिन खरना के अवसर पर व्रतधारी सुबह से निर्जला व्रत रखकर संध्या में केला के पत्ता पर खीर, रोटी आदि का भोग लगाकर छठी मैया को अर्पित किया। इस महाप्रसाद को व्रतधारी ग्रहण करके 36 घंटा का निर्जला व्रत का शुरू किया। कल व्रतधारी छठ घाट पहुंचकर संध्याकालीन भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेगी।

आधुनिक भारत के जिन्ना हैं अखिलेश यादव, हिंदुओं को बांटने की करते हैं राजनीति : भाजपा

लखनऊ (संवाददाता)। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओवैसी–चंद्रशेखर के गठबंधन के पीछे अखिलेश यादव की जिन्नावादी मानसिकता है। वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह जिन्ना ने देश को बांटने का काम किया था, उसी तरह अखिलेश यादव अब हिंदू समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। सनातन को गाली देना, लोगों को अपमानित करना और घुसपैठियों से गले मिलना ही अखिलेश यादव की पहचान है। वहीं, बीजेपी प्रवक्ता अंकुश त्रिपाठी ने सपा पर तुष्टीकरण और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2027 में यूपी की जनता अखिलेश यादव को करारा जवाब देगी। अंकुश त्रिपाठी ने कहा कि भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के डीएनए में है।

उत्तर मध्य रेलवे

टेण्डर संख्या : 230-वि0/कण्डि0/प्रयागराज/ई-टेण्डर/2026/674 दिनांक : 13.11.2026

ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/कण्डि0/उमण्रेo/प्रयागराज, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्न कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

निविदा सं0 : 230-कण्डि0-कार्य ठेका-1063-2026	अनुमानित लागत : रू0 80,84,490.00
कार्य का विवरण : प्रयागराज मंडल के पंडित दीन दयाल उपाध्याय-झींगक खंड में पुराने/खामजोर टैटेनरी तार को बदलने का कार्य (4th Call)।	
बिड सुरक्षा राशि : रू0. 1,61,700.00	कार्य अवधि : 12 महीना
बोली प्रणाली : एक पैकेट	निविदा बन्द होने की तिथि तथा समय : 04.12.2026, 14:00 बजे
निविदा खुलने की तिथि तथा समय : 04.12.2026, 15:00 बजे	

नोट :- 1. उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रपत्र सहित) वेबसाइट www.ireps.gov.in पर निविदा खोलने की तिथि से 21 दिन पहले से उपलब्ध होगा। 2. उपरोक्त निविदा में ई-बिड के अलावा किसी अन्य रूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु बेन्डरों को चाहिए कि वे अपने आपको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकृत करायें। 3. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए IREPS की वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क किया जा सकता है। 2587/26 (C)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

उत्तर मध्य रेलवे

टेण्डर सं. : 230-वि0/कण्डि0/प्रयागराज/ई टेण्डर/2026/676 दिनांक : 13.11.2026

ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/कण्डि0/उमण्रेo/ प्रयागराज, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्न कार्य हेतु ई निविदा आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है -

निविदा सं0 : 230-कण्डि0-कार्य ठेका-1065-2026

कार्य का विवरण : प्रयागराज मंडल के मंझराक (MXK) - धिपियाना बुजुर्ग (CPYZ) सेक्शन में OHE की विश्वसनीयता में सुधार के लिए पुराने और खराब हो चुके घटकों (जैटेनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर सहित) का नवीनीकरण और मुड़े हुए, झुके हुए और क्षितिकली इम्प्लान्टेड मास्ट्स को बदलने का कार्य (2nd Call)।

अनुमानित लागत : ₹ 3,07,37,008.80	बिड सुरक्षा राशि : ₹ 6,14,800.00
कार्य अवधि : 12 महीना	बोली प्रणाली : एक पैकेट
निविदा बन्द होने की तिथि तथा समय : 04.12.2026, 14:00 बजे	
निविदा खुलने की तिथि तथा समय : 04.12.2026, 15:00 बजे	

नोट :- 1. उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रपत्र सहित) वेबसाइट www.ireps.gov.in पर निविदा खोलने की तिथि से 21 दिन पहले से उपलब्ध होगा। 2. उपरोक्त निविदा में ई-बिड के अलावा किसी अन्य रूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु बेन्डरों को चाहिए कि वे अपने आपको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकृत करायें। 3. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए IREPS की वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क किया जा सकता है। 2589/26 (PH)

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

सम्पादकीय.....

फिर दहशत की दस्तक

भारत विरोध को प्राणवायु बनाने वाले पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह भारत पर घात का कोई मौका चूकेगा। पाक प्रायोजित आतंक का चेहरा एक बार फिर जम्मू–कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले में उजागर हुआ है। किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ की हत्या और कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की पोस्ट पर हमले की हालिया घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। करीब चौबीस घंटे के भीतर हुई ये घटनाएं बताती हैं कि जम्मू–कश्मीर में सुरक्षा हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। ये घटनाएं एक बार फिर याद दिलाती हैं कि सामान्य स्थिति और स्थायी शांति के दावों से इतर इलाके में आतंकवाद के रक्तबीज मौजूद हैं। दुखद ही है कि लापता होने के एक दिन बाद दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों के गोलियों से छलनी शव बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सीआरपीएफ की चेकपोस्ट पर हुए हमले में तीन जवान घायल हुए हैं। निस्संदेह,यह हमारी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के लिये नई चुनौती है। उल्लेखनीय है कि इससे ठीक एक साल पहले राजधानी में लाल किले के पास एक कार धमाके में ग्यारह लोगों की जान चली गई थी। कालांतर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनएआई की व्यापक जांच के बाद पता चला था कि विस्फोट की घटना में जम्मू–कश्मीर स्थित पुलवामा के एक डॉक्टर की मुख्य भूमिका रही थी। बहरहाल, जम्मू–कश्मीर में हालिया आतंकी हमलों की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार के उस दावे पर सवाल उठाये हैं, जिसमें कहा गया था कि जम्मू–कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो चुका है। ऐसे वक्त बयानबाजी से आगे बढ़कर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने, सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि स्थानीय समुदायों की चिंता पर विशेष ध्यान दिया जाए। निस्संदेह, आज के आधुनिक उन्नत तकनीक के युग में आतंकवाद से लड़ाई के लिये तमाम विकल्प सुरक्षा बलों के पास मौजूद हैं। लेकिन स्थानीय समाज में घुल–मिल कर रहने वाले आतंकियों तक पहुंच बनाने के लिये लोकल संपर्क सूत्रों की बड़ी भूमिका होती है। कोई भी केंद्रीय सत्ता स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने में असहजता महसूस करेगी। पाकिस्तानी सीमा से लगने वाले दूर–दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे बिना किसी भय व दबाव के सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग करें। निस्संदेह, आतंकवाद को हराने के लिये उनकी सुरक्षा, उनका भरोसा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि जम्मू–कश्मीर की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाये रखने के लिये कानून–व्यवस्था व शांति बनाये रखना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने देखा था कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी की आर्थिकी को भारी चोट पहुंची थी। जो अब धीरे–धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। देश के विभिन्न भागों व विदेशों से आने वाले पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने लौटने लगे थे। निर्विवाद रूप से किश्तवाड़ जैसे इलाकों में पर्यटन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। लेकिन गाहे–बगाहे होने वाले आतंकी हमले व हिंसा पर्यटकों को दूर रख सकती है। इससे विकास की गति बाधित होती है और स्थानीय लोगों की आजीविका संकट में पड़ जाती है। भले ही अभी तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिल पाया हो, लेकिन इसके बावजूद घाटी के लोगों का भरोसा हासिल करना बेहद जरूरी है। खासकर स्थानीय लोगों को सीमा पार से पोषित आतंकवाद के खात्मे के साथ कानून–व्यवस्था में भरोसा दिलाना जरूरी है। इस केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों से निपटने और जनता का भरोसा फिर से बहाल करने के लिये ठोस और कारगर रणनीति की जरूरत है। इसमें दो राय नहीं कि सीमाओं की सुरक्षा करने और घुसपैठ को रोकने में सेना व सुरक्षा बलों ने काफी हद तक सफलता पायी है, लेकिन स्थानीय समाज में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से निबटना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

विदेशी पत्रकार के भारत आने पर रोक

नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग एक बार फिर चर्चा में हैं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार द्वारा हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित श्भारत समिटश में देश और दुनिया की कई जानी–मानी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है और अलग–अलग विषयों पर उनके भाषण या व्याख्यान हैं। हेले लिंग को इस समिट में श्मीडिया के भविष्य और प्रेस की आजादीश पर एक पैनलिस्ट के तौर पर शामिल होना था। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए हेले लिंग ने जानकारी दी कि उनके एयरपोर्ट निकलने से 10 मिनट पहले नार्वे स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हें जानकारी दी कि उनका वीजा रद्द किया जाता है और वे अब भारत नहीं जा सकती है। हेले लिंग ने इस पूरे मामले में गृहमंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि उन्हें गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही भारत आने से रोका गया है। हेले लिंग ने अपने वीडियो में अनुमान लगाया है कि इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नार्वे यात्रा के दौरान उन्होंने मोदी से प्रेस की आजादी से जुड़े सवाल किए थे, क्या इसी वजह से उनकी यात्रा रोकी गई है या फिर जून–जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में उन्होंने संपादकीय लेख लिखे, इस वजह से मोदी सरकार ने उनका वीजा रद्द किया है या सीजेपी के अभिजित दिपके का इंटरव्यू हेले लिंग ने लिया है, यह बात मोदी सरकार को नागवार गुजरी है। अपने वीडियो में हेले लिंग ने यह भी कहा है कि अमित शाह अब गेंद आपके पाले में है। लिंग ने अमित शाह से मामले में हस्तक्षेप करने और उन्हें भारत आने की अनुमति देने की अपील की। उन्होंने कहा कि समिट में उनके बोलने का कार्यक्रम 48 घंटे बाद है और वह अगली उपलब्ध उड़ान से हैदराबाद पहुंच सकती हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अमित शाह, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शायद हेले लिंग उनकी नजर में इतनी अहमियत नहीं रखतीं कि उनकी पोस्ट में उठाए सवालों का जवाब दें, या फिर हेले लिंग एक पत्रकार के तौर पर मोदी सरकार को अब इतना डराती हैं कि उन्हें भारत आने से ही रोक दिया गया है। असलियत जो भी हो, इतना तो तय है कि हेले लिंग को आने से रोककर मोदी सरकार ने अपना ही नुकसान करवाया है। अगर वे तेलंगाना आतीं और अंग्रेजी में अपना भाषण देतीं, तो उस पर सीमित चर्चा ही होती, क्योंकि एक राज्य के कार्यक्रम में किसी वक्ता ने क्या कहा है, इस पर कम लोगों का ही ध्यान जाता। लेकिन अब मोदी सरकार के डर के कारण यह मुद्दा वैश्विक स्तर पर चर्चा में आ गया है। हेले लिंग को रोकना महज स्वतंत्र पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं माना जाएगा, यह विदेशी मीडिया में मोदी की नकारात्मक छवि बनाएगा। देश में तो मीडिया का बड़ा हिस्सा उनके मालिकान के कारण मैनेज किया जा चुका है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में मीडिया की स्वतंत्रता और साख अब भी कायम है। हेले लिंग को हैदराबाद के मंच से जो बातें कहनी थीं अगर वे नॉर्वे में बैठकर ही सोशल मीडिया के जरिए कहें तो अब दुनिया और गौर से उनकी बात सुनेगी। हेले लिंग मीडिया के भविष्य और प्रेस की आजादी के साथ अब यह भी दुनिया को बताएंगी कि कैसे उनकी आवाज को मोदी सरकार ने रोकने की कोशिश की। क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रेस की आजादी और लोकतंत्र की मजबूती आपस में जुड़े हुए हैं। उनकी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि भारत में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिशें हो रही हैं। प्रधानमंत्री प्रेस कांफ्रेंस नहीं करते यह एक शर्मनाक तथ्य है। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबमें कोई न कोई खामी रही, उनके फैसलों पर उंगलियां उठीं, जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा और अखबारों–चौनलों में उन पर नकारात्मक खबरें चलाई गईं। लेकिन बावजूद इसके कभी किसी प्रधानमंत्री ने इतने लंबे अर्से तक प्रेस को सीधे सवाल नहीं पूछने दिए। मोदी ने तो अपना बचाव करने के लिए धन और सत्ता की शक्ति के दम पर पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की ही है, इसके लिए वे पत्रकार और मीडिया मालिक भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जो करोड़ों की कमाई और अन्य लाभ के लिए अपने पेशे से बेईमान करने से नहीं हिचके। जब मई में हेले लिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से इतना ही पूछा था कि आप प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते, तो उस पर भारत में बैठे पिक्कू पत्रकारों ने हाय तौबा मचाई थी। हेले लिंग को चौनल पर बुलाकर उनसे अपमानजनक तरीके से सवाल–जवाब किए गए, उनके भारत संबंधी ज्ञान पर सवाल उठाए गए। मानो लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब भी मोदी सरकार की किरकिरी हुई थी और अब फिर से वही मौका सरकार ने खुद दे दिया है। वैसे हेले लिंग ने अब अमित शाह पर जिम्मेदारी डाली है कि वे उन्हें भारत आने की इजाजत दें, देखना होगा कि अमित शाह क्या फैसला लेते हैं।

जिंदगी से जुड़े मुद्दे भारी पड़े

राजेश पांडेय

अभी हाल कुछ देशों में हुए चुनावों ने नफरत और भेदभाव की राजनीति के खिलाफ स्पष्ट संकेत दिए हैं। दक्षिणपंथी राजनीति को जबर्दस्त आघात पहुंचाया है। वोटर ने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों और प्रश्नों को अहमियत दी है। उसने समाज को नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर बांटने की कोशिशों को ठुकराया है। अमेरिका, ब्राजील, सर्बिया और इजराइल के चुनाव नतीजे इन स्थितियों पर रोशनी डालते हैं। ये परिणाम भारत जैसे देश में इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देने वालों के लिए सबक हो सकते हैं। किसी देश में लोगों ने अल्पसंख्यकों, दूसरे देशों से आए इमिग्रांट्स के विरुद्ध भावनाएं भड़काने का विरोध किया है तो कहीं बेरोजगारी, महंगाई और रहन–सहन के बढ़ते खर्च पर गुस्सा जताया गया है। असंतोष की लहर को युवाओं ने भी आगे बढ़ाया है। दुनिया खासकर लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक,आर्थिक स्थिति पर अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में अमेरिकी चुनाव का वैश्विक महत्व है। वहां संसद के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक पराजय से सवाल उठता है, क्या विदेशियों और इमिग्रेशन की राजनीति ने वोटर पर असर डाला है? क्या शासन तंत्र में अरबपतियों के दबदबे और ईरान युद्ध ने वोटर को बेचैन किया है? मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी को अक्सर हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन, इतनी जबर्दस्त हार पहले किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में नहीं हुई थी। सीनेट और प्रतिनिधि सदन पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण खत्म हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने 37 साल में पहली बार टेक्सास राज्य में सीनेट की कोई सीट जीती है। डेमोक्रेट अब्दुल अल सैयद ने मिशिगन से चुनाव जीतकर अमेरिका के पहले मुस्लिम सांसद होने का इतिहास बनाया है। चुनाव परिणामों का अमेरिका की फेडरल सरकार के कामकाज पर असर पड़ सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को विधेयक पारित कराने के लिए डेमोक्रेट्स पर निर्भर होना पड़ेगा। वैसे, राष्ट्रपति को असीमित अधिकार होते हैं। वे संसद से पास कानूनों को वीटो कर सकते हैं। लेकिन हर मुद्दे पर टकराव से रिपब्लिकन पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। यों भी पार्टी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का विरोध बढ़ रहा है। ट्रम्प ने नतीजों के बाद कहा कि हमें डेमोक्रेट्स का सहयोग लेना पड़ेगा। वे स्वीकार करते हैं, उनकी सरकार द्वारा दूसरे देशों से आए इमिग्रांट्स पर सख्ती को लोगों ने पसंद नहीं किया है। इमिग्रेशन डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीति का मुख्य मुद्दा रहा है। वे 2016 से 2020 के बीच राष्ट्रपति रहते हुए इमिग्रांट्स के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे। 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को जीवित रखा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मैगा) के नाम से मशहूर उनके समर्थक भी इमिग्रांट्स का विरोध करते हैं। लेकिन दो साल के भीतर लोगों ने इस मुद्दे को भुला दिया। ईरान युद्ध के कारण तेल, गैस के मूल्य तेजी से बढ़े हैं। मकान किराया सहित जीवन के लिए जरूरी अन्य चीजों की बढ़ती कीमतों ने लोगों को उद्वेलित किया। ट्रम्प इन सबसे बेखबर थे। 2024 के बाद ट्रम्प सरकार की इमिग्रेशन विरोधी एजेंसी आईसीई ने कई राज्यों में छापे मारने का कार्यक्रम चलाया। अवैध इमिग्रांट्स को देश से बाहर निकालने का आक्रामक अभियान छेड़ा गया। हालांकि इसका जमकर विरोध भी हुआ। ट्रम्प ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चुनाव प्रचार में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ट्रम्प ने एक रैली में कहा, अगर डेमोक्रेट्स और अल सैयद चुनाव जीतते हैं तो वे अमेरिका में जेहादियों को ले आएंगे। लोगों का क्रिसमस मनाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी यह मुद्दा गर्म रखा। ट्रम्प के विभाजनकारी अभियान को देखते हुए अन्य रिपब्लिकन उम्मीदवारों ने भी इमिग्रांट्स और मुसलमानों को निशाना बनाया। ट्रम्प ने चुनाव से पहले कुछ राज्यों में चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन (जेरीमांडरिंग) कराया। इससे भी अंतिम नतीजों पर फर्क नहीं पड़ा। अपार धन की ताकत भी चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकी। रिपब्लिकन पार्टी को कई अरबपतियों ने डेमोक्रेट्स के मुकाबले ज्यादा चंदा दिया है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क ने चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा लगाए। उन्होंने अकेले टेक्सास में रिपब्लिकन केन पैक्सटन के चुनाव पर दो हजार करोड़ रुपए खर्च किए। स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स के मालिक मस्क के टेक्सास में कई कारोबार चलते हैं। फिर भी, पैक्सटन को डेमोक्रेट जेम्स टेलेरिको ने हरा दिया। ट्रम्प ने 2024–25 में मस्क को प्रशासन तंत्र की कार्यप्रणाली सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मस्क ने सरकारी सक्षमता विभाग (डीओजीई) के जरिये कई फैसले लिए। ज्यादा विरोध होने पर मस्क ने यह काम छोड़ दिया था। दूसरे देशों में भी ट्रम्प समर्थक नेताओं के पांव उखड़ गए हैं। ट्रम्प के सत्तारूढ़ होने से कई देशों में दक्षिणपंथी राजनीति को सहारा मिला था। संयोगवश उनमें से कुछ राजनेता अभी हाल में चुनाव हार गए हैं। मसलन सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वूसिक 12 साल सत्ता में रहने के बाद पराजित हुए। हंगरी में विक्टर ओर्बन पहले ही बाहर हो चुके हैं। ब्राजील में वामपंथी झुकाव रखने वाले राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने फ्लावियो बोलसोनारो को हरा दिया। डॉ. सिल्वा ने चार साल पहले फ्लावियो के पिता जेयर बोलसोनारो को हराया था। ट्रम्प ने फ्लावियो का खुलकर समर्थन किया था। ट्रम्प के एक अन्य प्रमुख सहयोगी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भी सत्ता में बने रहने की संभावनाएं कम हो गई हैं। चुनाव में उनके गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। वहां पूर्व सैनिक अधिकारी गादी आइजनकोट सरकार बनाने की जोड़–तोड़ में लगे हैं। राजनीतिक उथल–पुथल की हलचल कई यूरोपीय देशों में सामने आई है।

फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम में युवाओं, छात्रों ने आंदोलन छेड़े हैं। लेकिन फ्रांस में मेरीन ली पेन की दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी को काफी समर्थन मिल रहा है। जर्मनी में आल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) ने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की सरकार के सामने चुनौती खड़ी की है। यूरोप में मुख्यरूप से महंगाई और बेरोजगारी के विरूद्ध आवाज उठाई जा रही है। इधर, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक, सैनिक शक्ति के हिसाब से तो अमेरिका और भारत में काफी अंतर है। लेकिन, ट्रम्प की राजनीतिक प्राथमिकताओं और भारत में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काफी समानता है। मोदी सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी की अगुआई में हुए छात्रों के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा है। नीट पेपर लीक के विरोध में हुआ आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ था। इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुआई में विपक्षी दलों ने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग के साथ चल रहे अभियान का निशाना मोदी सरकार भी है। चुनाव प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं की कथा तो अनंत साबित हो रही है। चुनाव आयोग भी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आदेश जारी कर रहा है। इसके बावजूद अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है। चुनाव आयोग के बचाव में खड़ी भाजपा सवालों का जवाब देने की बजाय विपक्ष को देशद्रोही, अराजक और विदेशियों का टूलकिट घोषित कर रही है। भाजपा के सभी शीर्ष नेता कांग्रेस पर घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। वे दावा करते हैं, एसआईआर के तहत जिन 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनमें तीन करोड़ घुसपैठिये हैं। कांग्रेस इन लोगों को बचाने के लिए अभियान चला रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प भी डेमोक्रेटिक पार्टी पर इमिग्रांट्स को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हैं। भाजपा की हिंदुत्व राजनीति में अल्पसंख्यकों की हैसियत दोयम दर्जे की है। उनके खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर हर जगह घृणा फैलाने का अभियान चलाया जाता है। ट्रम्प भी अमेरिका में इमिग्रांट्स और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। एक और मामले में ट्रम्प और भाजपा नेतृत्व के बीच समानता है। यों तो अमेरिका पूंजीवाद का सबसे मजबूत दुर्ग है। लेकिन, ट्रम्प ने पूंजीवाद में नया अध्याय जोड़ा है। उनका प्रशासन मस्क जैसे कुछ अरबपतियों को ज्यादा तवज्जो देता है। अमेरिका में ट्रम्प के साथ मस्क हैं तो भारत में एनडीए सरकार अंबानी, अडानी और अन्य उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। ट्रम्प सरकार और मोदी सरकार के बीच समानताएं यहां खत्म नहीं होती हैं।

सुवेंदु सरकार की नई औद्योगिक नीति का स्वागत, लेकिन क्रियान्वयन सबसे महत्वपूर्ण

कुणाल बोस

इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल पर इतिहास का बोझ आज भी भारी है। इस पिछड़े राज्य के संदर्भ में, कार्लमार्क्स के श्द एटीनथब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्टश से एक उद्धरण देना उचित होगारू श्बीती पीढ़ियों की परंपराएं जीवित लोगों के दिमाग पर एक बुरे सपने की तरह हावी रहती हैं।श इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वाम मोर्चा के लंबे शासन और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के कार्यकाल में, पश्चिम बंगाल कभी भी औद्योगिक निवेशकृ खासकर बड़े उद्योगोंकृके लिए सही माहौल नहीं बना पाया। दोहराते हुए कहें तो, वाम मोर्चा के शासनकाल में जहां बड़े भारतीय औद्योगिक घरानों और विदेशी पूंजी को सत्ता में बैठे लोगों की नजरों में संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, वहीं उग्र ट्रेड यूनियन गतिविधियां निवेश में बाधा बनी रही। इसके बाद तृणमूल के शासन में निवेश और कामकाज का माहौल और भी खराब हो गया, जहां जबरन वसूली और गुंडागर्दी का बोलबाला रहा। एक उदाहरणरू 2008 में, जब वाम मोर्चा सत्ता में था, तब जेएसडब्ल्यू ने पश्चिम मेदिनीपुर के सालबोनी में एक बहुत बड़ी स्टील मिल लगाने के लिए लगभग 4,300 एकड़ जमीन हासिल की थी। लेकिन यह परियोजना कभी शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि कंपनी ओडिशा से लौह अयस्क की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पाई। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि यह समूह मुश्किलों में घिर गयाकृ उग्रवादियों की धमकियां, किसानों के विरोध–प्रदर्शन, और स्थानीय गुंडों द्वारा पैसे की मांग तथा सामान की आपूर्ति के ठेकों के लिए दबाव। ये सब वाम मोर्चा के अंतिम वर्षों और तृणमूल शासन, दोनों के दौरान हुआ। लेकिन, पिछली दो सरकारों के ये बुरे सपने आज की भाजपा राज्य सरकार को क्यों परेशान कर रहे हैं? कहा जाता है कि व्यापारिक घरानों की याददाश्त बहुत तेज होती है। किसी राज्य में श्ग्रीनफील्डश (नई) परियोजना में पूंजी लगाने या पहले से चल रही किसी इकाई में बड़ा निवेश करने के लिए, उनके लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना यह होता है कि वहां प्रबंधन का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित हो। दुर्भाग्य से, पश्चिम बंगाल – जो कभी मारवाड़ी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पसंदीदा जगह हुआ करता था– वहां 1960 से 1980 के दशक के बीच कई बड़े औद्योगिक घरानों (जैसे बिड़ला, सिंघानिया, थापर) और कंपनियों (जैसे ब्रिटानिया, फिलिप्स) ने राज्य छोड़ दिया। इसके कारण भी अच्छी तरह से दर्ज हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्योति बसु 23 साल से भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। देश के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी और वे उनका सम्मान भी करते थे, फिर भी बसु राज्य की औद्योगिक स्थिति में आ रही लगातार गिरावट को रोक नहीं पाए। बाहरी दुनिया को यह पता नहीं है कि किस बात ने बसु को सुधार के कदम उठाने से रोका। संभव है कि मार्क्सवादी पार्टी – जिसकी हर मामले में अंतिम राय होती है– ने बसु को इस गिरावट को रोकने के लिए पूरी छूट न दी हो। कारण चाहे जो भी रहा हो, पश्चिम बंगाल आज भी औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार है, और यहां से पूर्वोत्तर (नॉर्थ–ईस्ट) और उसके आगे के क्षेत्रों तक पहुंच भी मिलती है। इसलिए, पिछली दो सरकारों के दौरान आयोजित निवेशक सम्मेलनों में देश भर के व्यवसायी आते थे और निवेश का वादा करते थे। लेकिन ये वादे ज्यादातर कागजों तक ही सीमित रह गए और कभी जमीन पर नहीं उतरे। क्या मई 2026 में सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हालात बदले हैं? उनके पास 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 209 भाजपा विधायकों का समर्थन है। एक कहावत है कि असली परख इस्तेमाल करने पर ही होती है। वर्तमान मुख्यमंत्री से पहले के तीन मुख्यमंत्रियों– ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी– के कार्यकाल में बड़े उद्योगों में भारी निवेश के ढेरों वादे किए गए थे, और इसका नतीजा सबके सामने है। डॉ. बी. सी. रॉय के बाद की हर सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी आजादी के तुरंत बाद लगभग 30 प्रतिशत थी, जो अब गिरकर लगभग 3.5 प्रतिशत रह गई है। पिछले कुछ दशकों में, कभी मशहूर रही कई इकाइयां एक–एक करके घाटे में चली गईं और अंततरू बंद हो गईं। इनके बंद होने या ऐसी हालत में पहुंच जाने जहां से सुधार मुमकिन न हो, इसके कई कारण थे। इनमें शामिल हैं– गलत हाथों में जाना, खराब प्रबंधन, उत्पादों का पुराना हो जाना या बहुत महंगा पड़ना, और आधुनिकीकरण में कोई निवेश न करना। सरकार का उग्र ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों को अनदेखा करना भी निवेश के माहौल को खराब करने का एक बड़ा कारण रहा।

पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जड़ें होने के बावजूद, फिलिप्स का अब यहां कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। मेटल बॉक्स बहुत पहले ही खत्म हो गया। ब्रिटानिया, जिसने यहां अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, उसने भी कलकत्ता में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद कर दी। इसी तरह, कई बड़े केंद्रीय और राज्य उपक्रम भी यहां से चले गए, और अपने पीछे काफी मात्रा में ऐसी जमीन छोड़ गए जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राज्य में बहुत बड़ी औद्योगिक इकाइयां न लग पाने का एक बड़ा कारण यह है कि यहां सैकड़ों एकड़ की बड़ी जमीन के टुकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि राज्य प्रशासन अब ऐसी जमीन को वापस लेने की पहल कर रहा है जो बंद हो चुकी इकाइयों के पास बेकार पड़ी है। इनमें दुर्गापुर की एमएएमसी और हल्दिया की हिंदुस्तान फर्टिलाइजर जैसी इकाइयां शामिल हैं – जो दोनों ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। चूंकि केंद्र और पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी की सरकार है, इसलिए नई इकाइयों को बसाने के लिए खाली पड़ी जमीन को हासिल करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि स्थानीय सरकार के लिए उन सरकारी इकाइयों की जमीन वापस लेना आसान होगा, जो बंद हो चुकी हैं या घाटे में चल रही हैं। इस तरह से कुछ हजार एकड़ जमीन खाली हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल आधुनिक और बड़ी औद्योगिक इकाइयों को बसाने के लिए किया जा सकता है। अंबानी, अडानी और अनिल अग्रवाल जैसे उद्योगपतियों ने सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की है और पश्चिम बंगाल में बड़े निवेश का वादा किया है, जहां लंबे समय से पूंजी की कमी रही है। निवेश आने के लिए एक जरूरी शर्त यह है कि बड़े टुकड़ों में जमीन उपलब्ध हो, जिसे हासिल करने पर कोई कानूनी विवाद या सामाजिक टकराव न हो।



बढ़ते प्रदूषण के चलते बार- बार आती है छींक तो करें ये 5 उपाय

सर्दियां आते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। वहीं वायरल फ्लू होना और छींके आने की समस्या भी आम हो जाती है। लेकिन कई बार लोग छींक किसी एलर्जी के चलते भी बार– बार आती हैं। दरअसल ठंड के मौसम में वातावरण में धूल– मिट्टी और हानिकारक कण, बैक्टीरिया, धुआ, पोल्यूटेंट्स आदि जैसी चीजों के चलते संक्रमण की चपेट में आने का खतरा रहता है। कई लोगों का इस वजह से छींक– छींक कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे लोगों को काफी सावधानी बतरने की जरूरती होती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो ये घरेलू उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं....

भाप है असरदार

भाप लेने पर गले और फेफड़ों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। इससे लंग के फंक्शन में सुधार होता है, साथ ही नाक, गले और फेफड़ों की सूजन भी कम होती है। दिन में 2–3 बार भाप लेने से बहुत फायदा मिलता है। बेहतर होगा अगर आप भाप के पानी में नमक, पुदीना की तेल की 2– 3 बूदें भी डाल लें।

शहद से मिलेगी राहत

शहद भी वायरल फ्लू में छुटकारा दिलवाने का काम करता है। बस गुनगुने पानी में 1–2 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें या फिर दिन में 2–3 बार इसे अपनी हर्बल चाय में शामिल कर सकते हैं।

हल्दी भी है फायदेमंद

हल्दी में कई सारे औषधीय गुण हैं। इससे एलर्जी, नाक बंद और राइनाइटिस आदि के लक्षण कम होते हैं। आप गुनगुने पानी में हल्दी पाउडर मिलाकर पी सकते हैं और दूध में डाल भी इसका सेवन कर सकते हैं।

अदरक करें ट्राई

ठंड में चाय पीना तो सब को पसंद होता है। तो दिन में 2–3 बार अदरक वाली चाय पीएं , साथ ही इसे पानी में भी उबालकर पी सकते हैं। आप शहद लगाकर अदरक का टुकड़ा चबा भी सकते हैं। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी और एलर्जी से राहत मिलेगी।

इन बातों का भी रखें ख्याल

घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क जरूर लगा लें। घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। धूल– मिट्टी साफ करें और बेड शीट, कपड़ों को भी झाड़कर साफ कर लें।

शादी में दूल्हे जरूर अपनाएं ये मेकअप टिप्स, दुल्हन क्या सहेलियां भी हो जाएंगी लट्टू



इन दिनों शादी का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में हर दूल्हे और दुल्हन को अपनी शादी के दिन को खास बनाना चाहते हैं। क्योंकि सभी यह चाहते हैं कि अपनी शादी के दिन वह सबसे खूबसूरत और अलग दिखें। जिसके लिए महीनों पहले से तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। वहीं अगर बात लड़की होती है, तो हर लड़की अपनी शादी के लिए सबसे अच्छा पार्लर बुक करती है। जिससे कि उसका मेकअप अच्छा होने के साथ ही लांग–लास्टिक रह सके। लेकिन कई बार लड़के इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। अधिकतर लड़कों को यह पता नहीं होता है कि शादी के दिन उनको भी मेकअप करवाना होता है। जिससे कि वह भी ब्राइडल को टक्कर दे सकें और अपनी लाइफ के सबसे खास दिन पर सबसे स्मार्ट दिखें। हांलाकि पार्लर जाकर लड़कों को मेकअप करना पसंद भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको पार्लर जाकर मेकअप करना पसंद नहीं है तो आप घर पर भी मेकअप कर सकते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको घर पर ही मेकअप के कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। जिनको फॉलो कर आप अपने स्पेशल दिन को खास बना सकते हैं। जिससे कि आप अपनी शादी के दिन स्मार्ट और हैंडसम दिखें।

सबसे पहले अपनी शादी के दिन दूल्हे को अपने चेहरे को क्लीजिंग मिल्क की सहायता से साफ करना चाहिए। जिससे कि फेस की गंदगी अच्छे से साफ हो जाए। इसके बाद अपनी स्किन टाइप का टोनर फेस पर अप्लाई करें। ताकि आपकी स्किन ग्लो करे। टोनर अप्लाई करने के बाद अच्छी क्वालिटी का चेहरे पर फेस सीरम लगाएं। बता दें कि विटामिन सी का सीरम लगाने से आपकी स्किन खिली–खिली रहेगी। इसके बाद कलर करेक्टर का इस्तेमाल करें। जिससे कि आपके फेस पर अगर दाग धब्बे हों, तो वह छिप जाएं। वहीं आंखों के नीचे के काले घेरों को छिपाने के लिए कलर करेक्टर काम आएगा। शादी के दिन हर कोई अपनी खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाता है। वहीं दूल्हे–दुल्हन के साथ हर कोई तस्वीर लेता है। इसलिए अपनी आइब्रो को शेप जरूर दें। इससे आपका लुक और भी अच्छा लगेगा। फेस को शेप देने के लिए कंट्यूरिंग जरूर करें। ना सिर्फ दुल्हन बल्कि दूल्हे का भी चेहरा सही करने की जरूरत होती है। स्किन टाइप और स्किन टोन के हिसाब से फेस पर बेस और फांउडेशन अप्लाई करें। फाउंडेशन बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इससे आपकी स्किन अजीब दिख सकती है। आपके पूरे लुक को रूखे–सूखे होंठ खराब कर सकते हैं। इसलिए आप लिप बाम या फिर हल्के रंग की लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं।



पर्यटकों को आकर्षित करता है खूबसूरत हिल स्टेशन लोनावला

महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित लोनावला खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह पुणे से लगभग 64 किमी पश्चिम में और मुंबई से 96 किमी पूर्व में है। लोनावला को हार्ड कैंडी चिक्की के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। लोनावला आने के लिए पुणे जंक्शन से लोकल ट्रेनें उपलब्ध हैं। मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई–बेंगलुरु राजमार्ग भी लोनावाला से होकर गुजरते हैं। वर्तमान लोनावला सेउना (यादव) राजवंश का हिस्सा था। बाद में मुगलों को इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व का एहसास हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र को लंबे समय तक अपने पास रखा। इस क्षेत्र के किलों और ष्मावलाष योद्धाओं ने मराठा साम्राज्य और पेशवाओं के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1871 में लोनावाला और खंडाला हिल स्टेशनों की खोज लॉर्ड एलफिंस्टन ने की थी, जो उस समय बॉम्बे प्रेसीडेंसी के गवर्नर थे। लोनावाला और निकटवर्ती खंडाला सह्याद्रि पर्वतमाला में स्थित जुड़वां हिल स्टेशन हैं। हिल स्टेशन लगभग 38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। मानसून के मौसम में यहां पर्यटन चरम पर होता है। लोनावला नाम श्लेनीश शब्द से बना है जिसका अर्थ है गुफाएं और 'अवली' जिसका अर्थ है श्रृंखला। एक और दिलचस्प जगह तुंगी किला है, जो कर्जत गांव के पास मलिक अहमद द्वारा कब्जा किए गए किलों में से एक है। लोनावला के पर्यटन स्थलों की बात करें तो उनमें राजमाची प्वाइंट काफी मशहूर है। इस बिंदु से शिवाजी महाराज के किले, राजमाची (रॉयल टेराकोइओस) और आसपास की घाटी का दृश्य दिखाई देता है। राज्य परिवहन बस स्टैंड से राजमाची प्वाइंट और लोनावाला के बीच नियमित राज्य परिवहन बसें चलती हैं। वाघजई दारी भी यहीं स्थित है। राजमाची किला लोनावाला के नजदीक एक ऐतिहासिक किला है और मानसून के मौसम में बहुत सारे ट्रैकर्स को आकर्षित करता है। किले में दो अन्य किले भी शामिल हैं– श्रीवर्धन किला और मनरंजन किला। इसके अलावा, यह किला जुगनूओं के लिए जाना जाता है जो रात में आसपास को रोशन कर देते थे। रायवुड पार्क और शिवाजी उद्यान लोनावला में स्थित एक विस्तृत उद्यान है। इस बगीचे में कई ऊँचे पेड़ हैं, जिनमें से कुछ बहुत पुराने हैं। पार्क में एक पुराना शिव मंदिर है।

वलवन बांध

वलवन बांध एक ब्रिटिश निर्मित उद्यान है और एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है। इस बांध की दीवार के नीचे एक बगीचा है और यह शहर से 2 किमी दूर है। यह बांध बिजली पैदा करने के लिए सह्याद्रि की तलहटी में खोपोली बिजली स्टेशन को पानी की आपूर्ति करता है।

डेला एडवेंचर पार्क

डेला एडवेंचर पार्क भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क है जो लोनावला हिल स्टेशन में स्थित है। यह पार्क 36 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। डेला एडवेंचर पार्क करीब 52 साहसिक गतिविधियों की पेशकश करता है।

लोनावला झील

लोनावाला झील शहर से लगभग 1.6 किमी दूर प्राकृतिक दृश्यों से घिरी हुई है। सर्दी और गर्मी के महीनों के दौरान झील सूख जाती है और इसमें हरी घास उग आती है जिसका उपयोग वॉकर और जॉगर्स द्वारा किया जाता है। यह स्थान अपने स्ट्रीट फूड के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड में भुट्टे, स्मोक्ड कॉर्न, शेव्ड आइस (गोला), वड़ा पाव, चाट और अदरक चाय जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

ड्यूक की नाक

ड्यूक की नाक लोनावला से 12 किमी दूर है, जो मुंबई की ओर गाड़ी चलाते समय राजमार्ग से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। खंडाला के इस ऐतिहासिक स्थल को पैदल यात्री देखने आते हैं। इसे स्थानीय रूप से नागफनी (कोबरा का हुड) के रूप में भी जाना जाता है, इस चट्टान का नाम ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम पर रखा गया है, जिनकी नाक जैसी यह दिखती है।

टाइगर प्वाइंट

टाइगर्स लीप को टाइगर्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो 650 मीटर से अधिक की ढलान वाली एक चट्टान है। किंवदंती है कि एक बार एक बाघ द्वारा पीछा किए जाने पर मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी पहाड़ी पर से एक खाई में कूद गए और बाघ ने भी घाटी में छलांग लगा दी, तभी से इस स्थान को बाघ की छलांग का नाम दिया गया। बाघ की छलांग के ठीक आसपास एक छोटा–सा झरना है जो केवल मानसून के दौरान सक्रिय रहता है।

कार्ला गुफाएँ

लोनावाला के पास स्थित कार्ला गुफाएं तीसरी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित गुफा मंदिरों का एक परिसर है। यहां देवी एकवीरा देवी का एक मंदिर भी मौजूद है।

लोहागढ़ किला

मलावली रेलवे स्टेशन से लगभग 11.2 किमी की कठिन चढ़ाई आपको श्आयरन फोर्टश तक ले जाती है, जो कभी शिवाजी का दुर्जेय युद्ध स्थल था। किले से आसपास की पहाड़ियों और बस्तियों का दृश्य दिखता है।

विसापुर किला

लोहागढ़ किले के निकट विसापुर किला स्थित है जो लोहागढ़–विसापुर किले का हिस्सा है। विसापुर किला अपने जुड़वां लोहागढ़ की तुलना में बड़ा और अधिक ऊंचाई पर है। इसका निर्माण 1713–1720 ई. के दौरान बालाजी विश्वनाथ द्वारा करवाया गया था।

सिंह बिंदु

यह भूशी बांध और एम्बी वैली के बीच में एक दृश्य बिंदु है, जहां से एक गहरी घाटी और पहाड़ दिखाई देते हैं। यह स्थान भुने हुए मकई और प्याज के पकौड़ों के लिए जाना जाता है। इस पॉइंट पर कोई शेर नहीं है, लेकिन इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह लोनावाला के लायंस क्लब से जुड़ा है।

नारायणी धाम मंदिर

नारायणी धाम एक मंदिर है जिसका निर्माण 2002 में हिंदू देवी नारायणी के सम्मान में किया गया था। यह लोनावला रेलवे स्टेशन से 2 किमी की दूरी पर है। मंदिर में दुर्गा माता, सालासर बालाजी (हनुमान) और गणपति की मूर्तियाँ संगमरमर की संरचना में स्थित हैं।

तुंगरली बांध

यह झील और बांध मानसून के मौसम में जीवंत हो उठते हैं, जहां कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर चढ़कर बांध तक पहुंचते हैं। यह बांध ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था और इसमें पेड़ों और पहाड़ियों का एक शांत वातावरण है।



ड्राइव करके पहाड़ों में जाने से पहले करें इन 3 बातों पर गौर

लोगों को शांति और सुकून के लिए अकसर पहाड़ों पर जाना चाहते हैं। दिल्ली, पंजाब से खासकर के लोग वीकेंड पर बड़ी संख्या में शिमला, मनाली और मसूरी जैसी जगहों पर परिवार या दोस्तों के साथ कार में ही घूमने निकल पड़ते हैं। चाहे इन वादियों में कार में जाना और पहाड़ों के नजारे देखना अच्छा लगता हो, पर आपको जरूरत है कुछ बातों का ख्याल रखने की, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते बहुत घुमे हुए होते हैं तो कार चलाना मुश्किल होता है। यहां पर कार चलाते हुए बहुत सारा अटेंशन देने की जरूरत होती है, वरना जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में हम आपके लिए ये 3 टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए।

ब्रेक और गियर पर रखें कंट्रोल

जब भी आप पहाड़ों पर कार चलाते हैं तो गियर और ब्रेक का इस्तेमाल नॉर्मल की तुलाना में ज्यादा करें। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि कार की गियर और ब्रेक अच्छी स्थिति में हो। कोशिश करें कि पहाड़ों पर चढ़ते समय छोटे गियर में कार चलाएं और ब्रेक का भी पूरा ध्यान रखें। ब्रेक पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए।

पहाड़ों पर ओवरटेक ना करें

कोशिश करें कि दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक ना करें, क्योंकि हादसे का खतरा ज्यादा होता है। एगर ओवरटेक करना जरूरी ही है तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि सामने से कोई और गाड़ी न आ रही हो।

टायर हो अच्छी स्थिति में

अब कुछ ही दिनों में पहाड़ों में बर्फबारी में शुरु हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें कि कार के टायर अच्छी स्थिति में हो। ऐसे में टायर बर्फ में फिसलेंगे नहीं।



फेस्टिव सीजन में ट्राई करें ये ट्रेंडी और ईजी हेयरस्टाइल, देखने वाले नहीं हटा पाएंगे नजर

आज से यानी की धनतेरस के पर्व से दिवाली का त्योहार शुरू हो जाता है। इस साल 12 नवंबर 2023 को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली के मौके पर कई लोग अपने घर में दिवाली पार्टी का भी आयोजन करते हैं। दिवाली के दिन महिलाएं खास तौर पर अपने लुक्स पर ध्यान देती हैं। दिवाली के मौके पर महिलाएं अपने लुक को खास बनाने के लिए काफी कुछ करती हैं। लेकिन जब बात हेयर स्टाइल की आती है, तो कई बार समझ नहीं आता कि कौन सी हेयरस्टाइल हमें कैरी करना चाहिए। ऐसे में अगर आप भी अपने लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए हैं। इस आर्टिकल के जरिए हम आपको दिवाली के मौके पर कुछ ट्रेंडी और खूबसूरत हेयर स्टाइल के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे में आप भी इस तरीके से अपने बालों को स्टाइल कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं ट्रेंडी और खूबसूरत हेयर स्टाइल के बारे में...

फ्रेंच चोटी

दिवाली में ज्यादातर महिलाएं व लड़कियां एथनिक ड्रेस कैरी करती हैं। वहीं एथनिक ड्रेस पर फ्रेंच चोटी बेहद खूबसूरत लगती है। साथ ही फ्रेंच चोटी काफी कंफर्टेबल भी होती है। ऐसे में अगर आपक बाल छोटे हैं और आप इन्हें बांधना चाहती हैं। तो आप फ्रेंच चोटी बना सकती हैं। यह आपके लुक में चार चांद लगा देगा।

पोनी टेल

हांलाकि कई लोगों का मानना है कि सिर्फ वेस्टर्न लुक के साथ पोनी टेल अच्छी लगती है। लेकिन बता दें कि यह सोचना बिलकुक गलत है। दिवाली के मौके पर अपने लुक को खास बनाने के लिए आप राइट और लेफ्ट से पतली चोटी पोनी हेयर स्टाइल कैरी कर सकती हैं। कम समय में यह सिंपल हेयरस्टाइल काफी अच्छी लगेगी।

मेसी बन

अगर आप दिवाली के मौके पर साड़ी पहनने जा रही हैं, तो आपको मेसी बन बनाना चाहिए। आजकल साड़ी के साथ मेसी बन का ट्रेंड काफी चलन में है। साड़ी के साथ यह हेयर स्टाइल आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेगी। वहीं खुद को ट्रेडिशनल लुक देने के लिए आप मेसी बन को गजरे से सजा सकती हैं।

हाफ टाई हेयर स्टाइल

अगर आपके पास भी दिवाली में समय की कमी होती है, तो आप हाफ टाई हेयर स्टाइल ट्राई कर सकती हैं। इस हेयर स्टाइस को बनाना काफी ज्यादा आसान है। इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए आपको आगे के कुछ बाल लेकर पीछे की तरफ टाई करना है। फिर बाकी नीचे के बालों को सॉफ्ट कर्ल कर लें। यह हेयर स्टाइल आपको ट्रेंडी और ट्रेडिशनल दोनों लुक देने का काम करेगा।

वामिका गब्बी से कहा गया– 'तुम्हें कोई हीरोइन नहीं लेगा'



एक वक्त वामिका गब्बी को लगता था कि शायद वे एक्टिंग के लिए नहीं बनी हैं। लगातार रिजेक्शन मिल रहे थे और अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे। मुंबई में करीब 6–7 साल बिताने के बाद भी करियर उस मुकाम पर नहीं पहुंचा था, जिसका उन्होंने सपना देखा था। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे कहा गया कि अपने हुनर पर काम करो, क्योंकि तुम्हें कोई हीरोइन नहीं लेगा। इसी बीच नेटफ्लिक्स की दो सीरीज– 'बाहुबलीरू बिफोर द बिगिनिंग' और 'मिडनाइट्स चिल्ड्रन' से जुड़ने का मौका मिला, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट पर्दे तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि, एक अधूरी सीरीज ने उनके करियर की दिशा बदल दी। विशाल भारद्वाज की वर्कशॉप ने उन्हें एक्टिंग का नया नजरिया दिया, जबकि विक्रमादित्य मोटवानी की 'जुबली' से उन्हें हिंदी दर्शकों के बीच पहचान मिली। आज वामिका बड़े सितारों के साथ फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में नजर आ रही हैं। आज की सक्सेस स्टोरी में वामिका गब्बी के करियर और निजी जिंदगी से जुड़ी खास बातें। बचपन में कैमरे के सामने आईं, 'जब वी मेट' से शुरू हुआ सफर वामिका गब्बी का जन्म 29 सितंबर 1993 को चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता गोवर्धन गब्बी पंजाबी लेखक हैं। साहित्य और कला के माहौल में पली–बढ़ीं वामिका को बचपन से अभिनय में दिलचस्पी थी। उनके पिता मजाक में उन्हें ड्रामेबाज कहते थे। 2007 में रिलीज इम्तियाज अली की फिल्म 'जब वी मेट' वामिका के करियर की शुरुआती फिल्मों में शामिल थी। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर लीड रोल में थे। वामिका ने करीना के किरदार गीत की कजिन का छोटा–सा रोल निभाया था। सिनेमा एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में वामिका ने बताया था कि 'जब वी मेट' की शूटिंग के दौरान वे आठवीं क्लास में थीं। फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली आज भी उन्हें 'छोटी वाली' कहकर बुलाते हैं। उन्होंने बताया कि इम्तियाज ने 'जुबली' देखकर उनके अभिनय की तारीफ की, तो यह उनके लिए बेहद खास पल था। पहली फिल्म में छोटा रोल मिलने के बाद वामिका ने अभिनय जारी रखा। वे 'लव आज कल' (2009), 'मौसम' (2011) और 'बिट्टू बॉस' (2012) में नजर आईं। हालांकि, इन फिल्मों से उन्हें करियर को नई ऊंचाई देने वाली पहचान नहीं मिली। 'तुम्हें कोई हीरोइन नहीं लेगा', कम उम्र में सुननी पड़ी यह बात वामिका के शुरुआती करियर का एक किस्सा उनके संघर्ष को दिखाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शुरुआती फिल्मों में से एक की शूटिंग के दौरान उनकी उम्र करीब 16–17 साल थी। पूरी टीम डिनर के लिए बैठी थी। तभी एक शख्स उनके पास आया और कहा– अपने क्राफ्ट पर काम करो, अच्छी एक्टर बनना, क्योंकि तुम्हें कोई हीरोइन तो लेगा नहीं। कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले किसी भी कलाकार के लिए भविष्य को लेकर ऐसी टिप्पणी सुनना आसान नहीं होता। वामिका की कहानी ऐसे बयानों तक सीमित नहीं है। करियर में कई बार उन्हें अपने काम पर दोबारा विचार करना पड़ा। कभी सही रोल नहीं मिले, तो कभी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनने से पहले ही बंद हो गए। कई बार उन्हें लगा कि शायद वे सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही हैं। इसके बावजूद उन्होंने अभिनय जारी रखा। छोटे रोल से शुरुआत कर अलग–अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया और फिर हिंदी सिनेमा में लीड रोल हासिल किया। पंजाबी फिल्मों से पहचान मिली, साउथ सिनेमा में भी आजमाया हुनर हिंदी फिल्मों में शुरुआती काम के बाद वामिका ने पंजाबी सिनेमा में जगह बनाने की कोशिश की। 2013 में रिलीज पंजाबी फिल्म 'तू मेरा 22 मैं तेरा 22' में वे नजर आईं। फिल्म में उनके साथ अमरिंदर गिल और यो यो हनी सिंह थे। इसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों में लगातार काम किया। वामिका ने 'इश्क ब्रांडी', 'निका जैलदार 2' और अन्य पंजाबी फिल्मों से दर्शकों के बीच पहचान मजबूत की। उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में भी काम किया। तमिल फिल्म 'मलाई नेरथु मयक्कम' और मलयालम फिल्म 'गोधा' उनके क्षेत्रीय सिनेमा के सफर की अहम फिल्में हैं। अलग–अलग भाषाओं की फिल्मों में काम करने से वामिका को कई तरह के किरदार निभाने का अनुभव मिला। हालांकि, कई साल काम करने के बाद भी हिंदी सिनेमा में उन्हें मनचाही पहचान नहीं मिली। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में वामिका ने बताया था कि 2019 तक वे मुंबई में करीब सात साल बिता चुकी थीं। फिर भी उन्हें मनचाहा काम नहीं मिल रहा था। वे अपने अभिनय से संतुष्ट नहीं थीं और उन्हें लगने लगा था कि शायद कुछ और करना चाहिए। 2019 में एक्टिंग छोड़ने का मन बनाया, फिर मिला विशाल भारद्वाज का प्रोजेक्ट वामिका के करियर का अहम मोड़ 2019 में आया। उस साल उनकी पांच पंजाबी फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से तीन सफल रही थीं। इसके बावजूद वे अपने काम से खुश नहीं थीं। फिल्मफेयर को नवंबर 2023 में दिए इंटरव्यू में वामिका ने बताया कि उस दौर में वे करियर को लेकर उलझन में थीं। उनके पिता हमेशा कहते थे कि वही काम करना चाहिए, जिसमें खुशी मिले। वामिका ने सोचा था कि कुछ और फिल्में करके पैसे कमाएंगी और फिर दुनिया घूमने निकल जाएंगी। इसी दौर में उन्हें फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज के प्रोजेक्ट 'मिडनाइट्स चिल्ड्रन' के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला। यह प्रोजेक्ट लेखक सलमान रुश्दी के चर्चित उपन्यास पर आधारित था। वामिका के मुताबिक, उन्होंने शुरुआत में ऑडिशन को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि लगातार रिजेक्शन के बाद उन्हें इस बार भी चयन की उम्मीद नहीं थी। लेकिन किरदार के लिए सीन करते हुए उन्हें मजा आया। वे सहज महसूस कर रही थीं और यह अनुभव उन्हें पिछले ऑडिशन से अलग लगा। इसके बाद उन्हें बताया गया कि चुने गए कलाकारों को एक्टिंग कोच अतुल मोंगिया के साथ तीन दिन की वर्कशॉप करनी होगी। वामिका उसमें शामिल हुईं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह अनुभव अभिनय और करियर को लेकर उनका नजरिया बदल देगा। तीन दिन की वर्कशॉप से सीखा– बेहतर एक्टर बनने के लिए खुद को समझना जरूरी वामिका के लिए 'मिडनाइट्स चिल्ड्रन' का ऑडिशन बड़े प्रोजेक्ट में काम पाने के साथ–साथ अभिनय को नए सिरे से समझने का मौका भी था। उन्होंने बताया था कि वर्कशॉप के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि एक्टिंग का मतलब खुद को छिपाना या किसी दूसरे की नकल करना नहीं है। अभिनय बेहतर बनाने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। जब इंसान खुद के प्रति संवेदनशील, स्वीकार करने वाला और कम जजमेंटल होता है, तो वह अपने किरदार को भी बेहतर समझ पाता है। इस अनुभव से वामिका का अभिनय के प्रति उत्साह लौटा। जिस काम को छोड़ने के बारे में वे सोच रही थीं, उसी में उन्हें नई खुशी मिलने लगी। विशाल भारद्वाज ने भी उनके टैलेंट पर भरोसा जताया। फिल्मफेयर से बातचीत में वामिका ने बताया था कि प्लेटफॉर्म लोकप्रिय चेहरे की तलाश में था, लेकिन विशाल भारद्वाज उन्हें चुनना चाहते थे। वामिका के मुताबिक, उन्होंने उनके टैलेंट पर भरोसा जताते हुए कहा था कि इस लड़की में कुछ खास है। किसी अनुभवी फिल्ममेकर का भरोसा एक युवा कलाकार के लिए बड़ी बात होती है। वामिका के लिए यह सिर्फ रोल मिलने की खबर नहीं, बल्कि अपने अभिनय के दम पर आगे बढ़ने का भरोसा भी था। 'मिडनाइट्स चिल्ड्रन' बंद हुई, लेकिन वामिका के लिए नए रास्ते खुले 'मिडनाइट्स चिल्ड्रन' में वामिका को पार्वती के किरदार के लिए चुना गया था। वे प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही थीं, लेकिन शूटिंग शुरू होने से करीब एक महीने पहले इसे रोक दिया गया।



सैफ अली खान ने हाल ही में बालकनी में इलेक्ट्रिक गिटार बजाते हुए वीडियो शेयर किया। वह कुछ म्यूजिशियन के साथ फ्यूजन करते नजर आए। सैफ ने एक पीला इलेक्ट्रिक गिटार पकड़ा हुआ था, जिसके चारों ओर एम्पलीफायर और दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। वीडियो पर करीना कपूर खान ने रोमांटिक कमेंट किया। उन्होंने लिखा, "दुनिया का सबसे कूल पति कौन है? क्या मैं कह सकती हूं, मेरा?" वीडियो शेयर करने के साथ सैफ ने अपनी पोस्ट में मजाकिया अंदाज में लिखा, "ग्रूव मिल गया, टेम्पो खो गया, फिर भी बहुत मजा आया।" सैफ का म्यूजिक से जुड़ाव सैफ पहले भी कई मौकों पर म्यूजिक में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। उन्होंने गिटार बजाने का हुनर भी दिखाया था। सैफ रॉक बैंड्स के साथ परफॉर्म कर चुके हैं। इनमें परिक्रमा भी शामिल है। मई 2025 में करीना ने सैफ और अपने बड़े बेटे तैमूर अली खान की घर पर जामिंग करते तस्वीरें शेयर की थीं। करीना गन्स एन रोजेज के कॉन्सर्ट में नहीं जा सकी थीं। इसके बाद उन्होंने घर पर ही अपने म्यूजिशियन ढूंढ लिए। उन्होंने पिता–पुत्र की तस्वीरों के साथ लिखा था, "शायद मैं गन्स एन रोजेज मिस कर गई, लेकिन मेरे पास अपने बैंड के लोग हैं।" सैफ ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया था। सैफ की पहली पोस्ट पटौदी लाइब्रेरी को समर्पित थी। पोस्ट में वह लाइब्रेरी के अंदर पोज देते और पढ़ते नजर आए थे। 'कौन बनेगा करोड़पति' में जीता था घीसैफ हाल ही में अमिताभ बच्चन के टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में नजर आए थे। वह अक्षय कुमार के साथ अपनी फिल्म 'हाइवॉन' को प्रमोट करने पहुंचे थे।



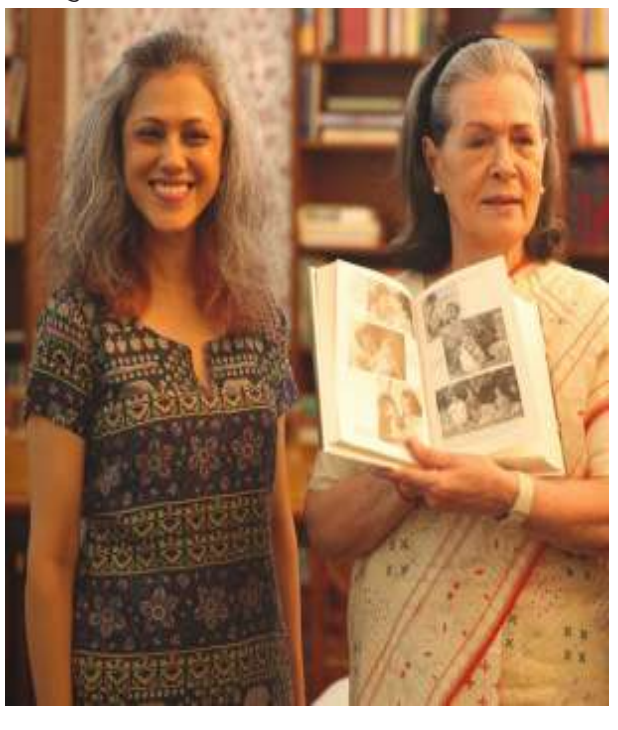
2026 में रिलीज हुई हॉलीवुड हॉरर फिल्म ऑब्सेशन ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. भारत में भी इस अंग्रेजी हॉरर फिल्म को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला. वहीं, थिएटर में रिलीज होने के बाद फिल्म अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. फिल्म की कहानी प्यार, जुनून और खौफ के इर्द–गिर्द घूमती है. अगर आपको डरावनी फिल्में देखना पसंद है, तो ये आपके लिए बेहतरी ऑप्शन हो सकती है. हिंदी में ओटीटी पर कब और कहां देखें ऑब्सेशन? फिल्म ऑब्सेशन 30 अक्टूबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी. इसे प्लेटफॉर्म के पीकॉक हब के जरिए देखा जा सकेगा. दर्शक इस फिल्म को अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में देख पाएंगे. इस बार फिल्म अपने ओरिजिनल अनकट वर्जन में रिलीज हो रही है. बता दें, भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ये फिल्म प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म पर किराए पर देखने के लिए भी उपलब्ध थी. अब जियो हॉटस्टार पर दर्शक इसे एक बार फिर देख सकेंगे. ऑब्सेशन को IMDB पर 7.8 की रेटिंग मिली है. फिल्म ऑब्सेशन की कहानी ऑब्सेशन एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है, जो अमेरिका में 15 मई और भारत में 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. करी बार्कर के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी निक्की और बेयर के इर्द–गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है. दरअसल, बेयर एक शापित चीज वन विश विलो का इस्तेमाल करके निक्की को उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर देता है. लेकिन उसकी यह ख्वाहिश धीरे–धीरे डरावने रूप में बदल जाती है और निक्की अपने रास्ते में आने वाले लोगों के लिए खतरनाक बन जाती है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में करीब 3,851.14 करोड़ रुपये की कमाई की और 65,360 शो में दिखाई गई. इसमें भारत में 100.96 करोड़ रुपये और विदेशों में 1,505 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई.



इंदिरा गांधी की बहू से कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत बनने तक...अब फिल्मी पर्दे पर दिखेगी सोनिया गांधी की कहानी, बनेगी तेलुगु फिल्म

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के कार्यकारी अध यक्ष जग्गा रेड्डी ने गुरुवार को घोषणा की कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा, बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव पर एक तेलुगु फीचर फिल्म बनाई जाएगी, जिसमें उनके जीवन और राजनीतिक सफर को दिखाया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान की। इस मौके पर उन्होंने संगारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आगे आने और फिल्म के निर्माण में योगदान देने की अपील की। इस दौरान, निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस संयोजक जुलाकंती अंजनेयुलु ने फिल्म के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये का योगदान देने की घोषणा की। जग्गा रेड्डी ने फिल्म निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 50 सदस्यीय समिति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख गांधी भवन के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) हरिप्रसाद करेंगे। उन्होंने पार्टी नेताओं से फंड जुटाने को कहा और कार्यकर्ताओं से बोले, आप लोग चुनावों में खर्च करते हैं, है ना? इसे भी वैसा ही एक खर्च समझें। आइए, बजट जुटाते हैं और एक अच्छा निर्देशक चुनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तैयारियां पूरी हो जाएंगी, तो वे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ को फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए आमंत्रित करेंगे। जग्गा रेड्डी ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी की आत्मकथा की प्रतियां मंगवाई जाएंगी और उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बांटा जाएगा, ताकि वे उनके जीवन और अनुभवों को और बेहतर ढंग से समझ सकें। जग्गा रेड्डी ने बताया कि यह फिल्म सोनिया गांधी के जीवन के विभिन्न चरणों को दिखाएगी, जिसमें इंदिरा गांधी की बहू और राजीव गांधी की... ...पत्नी, और राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी की मां।

उन्होंने बताया कि यह फिल्म दर्शकों के सामने उन त्रासदियों को लाएगी जिनका सामना इस परिवार ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद किया था। साथ ही, इसमें सोनिया गांधी द्वारा झेले गए संघर्षों, उनके द्वारा राहुल और प्रियंका की परवरिश, और उनके राजनीतिक सफर को भी दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने भारत जैसे विविध धर्मों, जातियों और भाषाओं वाले देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक व्यवस्था उतनी ही गहरी है जितना कि समुद्र। सोनिया गांधी ने इस राजनीति को समझा है। उन्होंने आगे कहा कि उनका राजनीतिक करियर काफी सफल रहा है। जग्गा रेड्डी ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के पद का कोई मोह नहीं था। राजीव गांधी की हत्या के बाद के दौर को याद करते हुए, जब पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, जग्गा रेड्डी ने कहा कि उस समय सोनिया गांधी ने इस पद को पाने की कोई इच्छा नहीं जताई थी। उन्होंने आगे याद दिलाया कि जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सत्ता में आया, तब भी जब कांग्रेस नेताओं ने उनसे प्रधानमंत्री बनने का आग्रह किया, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसकी जगह मनमोहन सिंह को यह मौका दिया। इस मौके को ठुकराने के उनके फैसले को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए, जग्गा रेड्डी ने कहा कि यह उनके राजनीतिक सफर के एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की रूपरेखा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के विचारों के आधार पर तैयार की गई थी। जग्गा रेड्डी ने आगे कहा कि लोग एक बार फिर गांधी परिवार से किसी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और सोनिया गांधी की भी यही इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें।



संक्षिप्त



ट्राई ने स्पैम पर कड़ा प्रहार किया, 1.24 लाख से अधिक टेलीकॉम कनेक्शन पर कार्रवाई

दूरसंचार नियामक ट्राई ने अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) पर अंकुश लगाने के लिए चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 1.24 लाख से अधिक दूरसंचार संसाधनों के खिलाफ कार्रवाई की और 374 संस्थाओं को एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने वित्त वर्ष 2026–27 की दूसरी (जुलाई–सितंबर) तिमाही की रिपोर्ट में कहा कि पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 1,10,325 दूरसंचार संसाधनों की आउटगोइंग सेवाएं 15 दिन के लिए प्रतिबंधित कर दी गईं। वहीं, बार–बार उल्लंघन करने पर 13,777 मोबाइल कनेक्शन एक साल के लिए काट दिए गए। नियामक ने इस दौरान 3,725 एसएमएस हेडर भी ब्लॉक किए। इसके अलावा, संदेश भेजने वाली 374 संस्थाओं को एक साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। इस अवधि में ये संस्थाएं नए दूरसंचार संसाधन हासिल नहीं कर सकेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई–सितंबर तिमाही में ट्राई को अवांछित वाणिज्यिक संचार से संबंधित 15.29 लाख शिकायतें मिलीं, जिनमें से 7.23 लाख शिकायतों को कार्रवाई योग्य पाया गया। इस दौरान देश के दूरसंचार नेटवर्क से 714.01 अरब कॉल और 702.28 अरब एसएमएस भेजे गए। शिकायतों की दर प्रति 10 लाख आउटगोइंग कॉल पर लगभग 2.14 रही। स्पैम की शिकायत दर्ज कराने के लिए ट्राई का 'डू नॉट डिस्टर्ब' (डीएनडी) ऐप सबसे प्रमुख माध्यम बना रहा। कुल शिकायतों में से 14.21 लाख यानी 92.9 प्रतिशत शिकायतें इसी ऐप के जरिये दर्ज की गईं। इस ऐप को 30 सितंबर तक 42.36 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका था। ट्राई ने बताया कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा तैनात कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित प्रणालियों ने तिमाही के दौरान 19.9 अरब इनकमिंग कॉल और एसएमएस को संभावित स्पैम के रूप में चिह्नित किया। इनमें 18.28 अरब कॉल और 1.62 अरब एसएमएस शामिल हैं। दूरसंचार कंपनियों ने संदिग्ध स्पैम भेजने वाली संस्थाओं को 45.9 लाख से अधिक चेतावनी संदेश भी जारी किए।

दालों की कीमतों पर सरकार सख्तः हर शुक्रवार बताना होगा कितना है स्टॉक, जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला

नई दिल्ली। देश में दालों की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने और बाजार में कृत्रिम किल्लत व जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक के बाद, सरकार ने सभी प्रकार की दालों के लिए अनिवार्य स्टॉक घोषणा की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत अब देश के सभी स्टॉकिस्ट, मिलर्स, आयातकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के साथ–साथ बड़ी रिटेल चेन को भी प्रत्येक शुक्रवार दालों के स्टॉक की जानकारी देनी होगी। शुक्रवार को उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और दाल मिलर्स, आयातकों, ट्रेडर्स, डीलर्स व बड़ी रिटेल चेन के प्रतिनिधियों के बीच करीब 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली। इस बैठक में बाजार में दालों की उपलब्धता और खुदरा कीमतों की समीक्षा की गई। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से स्टॉक की सही जानकारी दें और बाजार में आपूर्ति को सुचारू बनाए रखें। सरकार का मानना है कि इस साप्ताहिक खुलासे से बाजार में दालों की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। बंपर उत्पादन और भारी आयात के बावजूद क्यों महंगी हैं दालें? सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंपर पैदावार और भारी स्टॉक के बावजूद उपभोक्ताओं को महंगी दालें क्यों खरीदनी पड़ रही हैं। केंद्र के पास अभी 38 लाख टन दालों का सुरक्षित बफर स्टॉक उपलब्ध है।

आयात घटाने के लिए हाइड्रोजन और मेथनॉल को मिले प्राथमिकता

एक नए अध्ययन के अनुसार, आयातित ईंधन और उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए कोयले से हाइड्रोजन, एसएनजी, मेथनॉल और अमोनिया उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अध्ययन सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण योजना के तहत निवेश का मार्गदर्शन करेगा। इसमें हाइड्रोजन को शीर्ष प्राथमिकता देकर औद्योगिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आयातित ईंधन, उर्वरकों और औद्योगिक रसायनों पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए कोयले से हाइड्रोजन, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी), मेथनॉल और अमोनिया के उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक नए अध्ययन में यह बात कही गई है। सेंटर फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च (सी–डीईपी) और सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज (सीडब्ल्यूएस) के इस अध्ययन में कोयले से बनने वाले 23 उत्पादों को आठ आर्थिक, औद्योगिक और रणनीतिक मानकों पर श्रेणीबद्ध किया गया है। इस पहल का मकसद सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाली सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की योजना के तहत निवेश का मार्गदर्शन करना है। अध्ययन में कहा गया कि हाइड्रोजन सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उत्पाद के रूप में उभरा है। इसके बाद एसएनजी, मेथनॉल, अमोनिया, डाइमिथाइल ईथर (डीएमई), तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), रसोई गैस (एलपीजी), यूरिया और डीएपी (डाइअमोनियम फॉस्फेट) का स्थान है। ये सिफारिशें ऐसे समय में आई हैं जब भारत आयातित ऊर्जा और उर्वरक उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कोयला गैसीकरण क्षमता का विस्तार करना चाहता है।

सी–डीईपी के अध्यक्ष जयजीत भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार की 37,500 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता को देखते हुए ऐसे उत्पादों की पहचान करना महत्वपूर्ण हो गया है जो सबसे अधिक आर्थिक लाभ दे सकें। उन्होंने कहा, हमारा विश्लेषण निवेश को उन उत्पादों की ओर मोड़ने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो आयात को कम कर सकते हैं, घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत कर सकते हैं और भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता को समर्थन दे सकते हैं।

टीम इंडिया के खिलाफ अंतिम ODI जीतकर सीरीज बराबर करने उतरेगा न्यूजीलैंड : विल यंग



न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज विल यंग ने कहा कि उनकी टीम पांचवें और अंतिम वनडे में भारत के खिलाफ जीत की लय बरकरार रखकर शृंखला बराबर करने उतरेगी। उन्होंने बताया कि परिस्थितियों के अनुरूप ढलना पिछली बड़ी जीत की कुंजी रहा। प्रमुख खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के बावजूद यह अन्य खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका होगा।

आक्रामक सलामी बल्लेबाज विल यंग ने कहा कि न्यूजीलैंड रविवार को पांचवें और अंतिम एकदिवसीय में भारत के खिलाफ अपनी पिछली शानदार जीत की लय बरकरार रखते हुए पांच मैच की शृंखला बराबर करने की कोशिश करेगा। भारत फिलहाल शृंखला में 2–1 से आगे है। यंग ने मैच के बाद कहा, ''यह भारत के खिलाफ हमारी सबसे एकतरफा जीत में से एक थी और भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार में से भी एक थी। आप कभी इस तरह के रिकॉर्ड बनाने के इरादे से मैदान पर नहीं उतरते लेकिन बाद में इस पर गौर करना अच्छा लगता है।'' मैच विजयी शतक लगाने वाले यंग ने कहा कि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना इस बड़ी जीत की कुंजी रहा। उन्होंने कहा, ''एकदिवसीय प्रारूप में हमारी पूरी क्रिकेट शैली परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने पर आधारित है। मैंने अपनी पारी की शुरुआत में ऐसा करने में सफलता हासिल की। जाहिर है किस्मत ने भी हमारा थोड़ा साथ दिया लेकिन हमने अच्छी नींव रखी।'' यंग ने कहा, ''हमने महसूस किया कि ऑकलैंड और वेलिंगटन में खेले गए शुरुआती दो एकदिवसीय की तुलना में यहां की पिच थोड़ी बेहतर थी और हमने ऐसा स्कोर खड़ा किया जिसे हम प्रतिस्पर्धी मानते थे।'' न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 89 रन पर सिमट गई थी। यंग को आकिब नबी के दूसरे ओवर में लगातार दो गेंद पर जीवनदान मिला था। न्यूजीलैंड अंतिम एकदविसीय में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतरना होगा क्योंकि वे आगामी टेस्ट शृंखला की तैयारी के लिए रवाना होंगे। हालांकि यंग ने कहा कि टीम में होने वाले बदलाव अन्य खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देंगे। उन्होंने कहा, ''टीम में कुछ बदलाव होंगे लेकिन मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ शृंखला बराबर करने का मौका निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है।'' यंग ने मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले मैट हेनरी की भी जमकर तारीफ की।

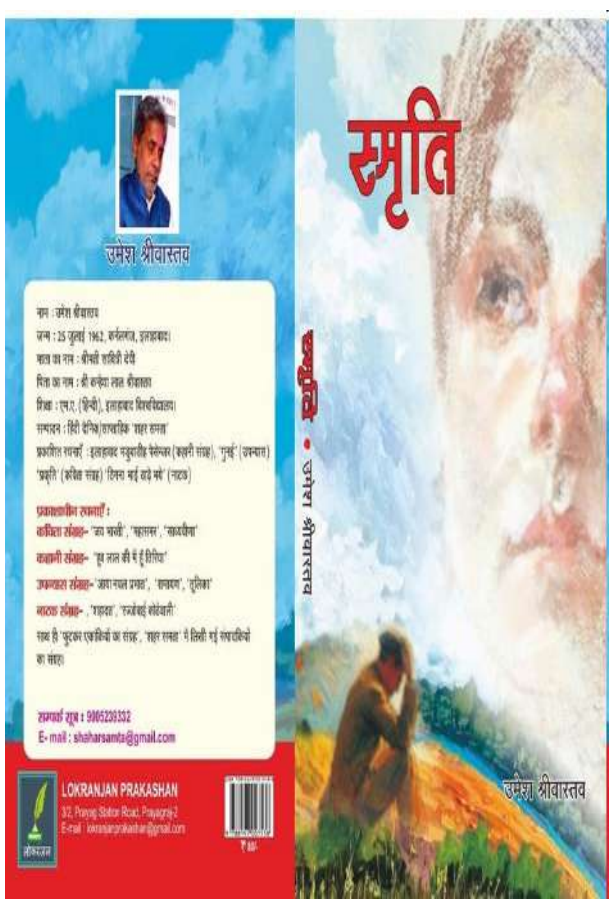
न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल हुएगुरनूर बरार, कुलदीप यादव रिलीज

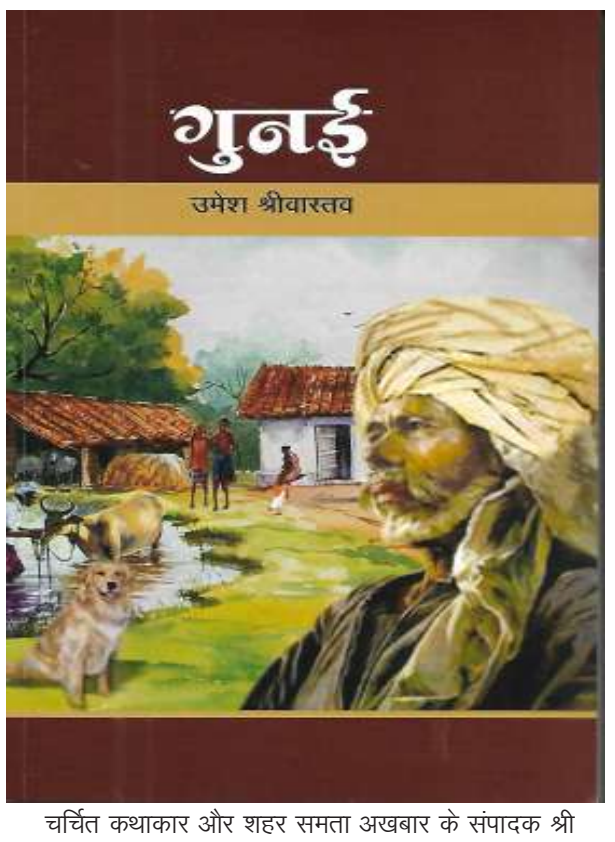
न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए स्पिनर कुलदीप यादव को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए रिलीज कर दिया गया। वहीं चोट से उबरकर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी टीम से जुड़ गए हैं।



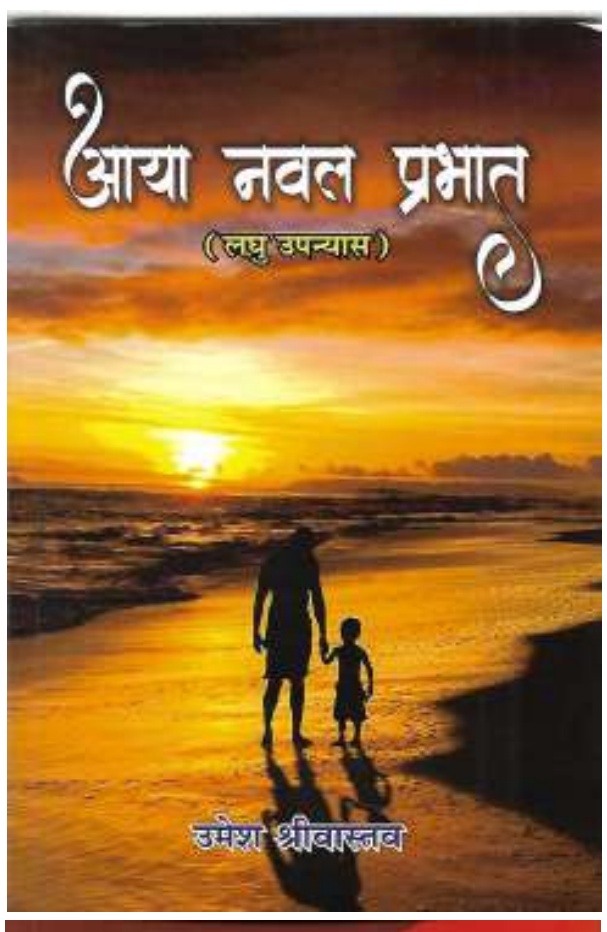
तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की शृंखला के लिए शनिवार को भारतीय टीम में शामिल किया गया जबकि स्पिनर कुलदीप यादव को रिलीज (टीम से हटा लेना) कर दिया गया क्योंकि इस शृंखला में तेज गेंदबाजों के अनुकूल पिचें मिलने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बयान में कहा, ''पुरुष चयन समिति ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर 2026 से वेलिंगटन में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की शृंखला के लिए भारतीय टीम में गुरनूर बरार को शामिल किया है।'' बयान के अनुसार, ''कुलदीप यादव को भारत में जारी घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए टेस्ट टीम से रिलीज किया जाएगा।'' टेस्ट टीम में चयन के बाद बरार रविवार को माउंट मोनगानुई में होने वाले पांचवें और अंतिम एकदिवसीय मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। बरार की हार्ड लेंथ से अतिरिक्त उछाल हासिल करने की क्षमता मेजबान टीम के बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। संभावना है कि भारत शृंखला के पहले टेस्ट में प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में चार तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेगा। आकाश दीप, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम का हिस्सा हैं। तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए कुलदीप के दो टेस्ट मैच की अंतिम एकादश में जगह बनाने की संभावना नहीं थी। ऐसे में वह एकदिवसीय शृंखला के बाद घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए भारत लौटेंगे। बीसीसीआई ने बताया कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी बेसिन रिजर्व में होने वाले मुकाबले से पहले टीम से जुड़ गए हैं। पंत साइड स्ट्रेन (मांसपेशियों की चोट) की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाने के कारण भारत ए की शृंखला में नहीं खेल सके थे। भारतीय टेस्ट टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को भारत ए की शृंखला में खेलकर अभ्यास का अच्छा मौका मिला। हालांकि कप्तान शुभमन गिल भारत ए की शृंखला में नहीं खेले लेकिन लाल गेंद से क्रिकेट की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तीन मैच के बाद एकदिवसीय टीम से हट गए थे। दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा।

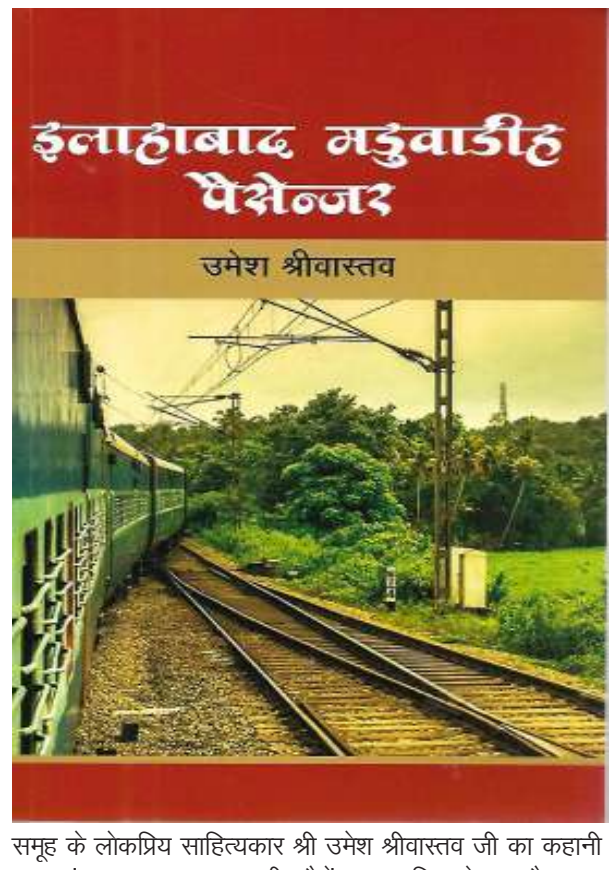
भारत की संशोधित टेस्ट टीम– शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार।



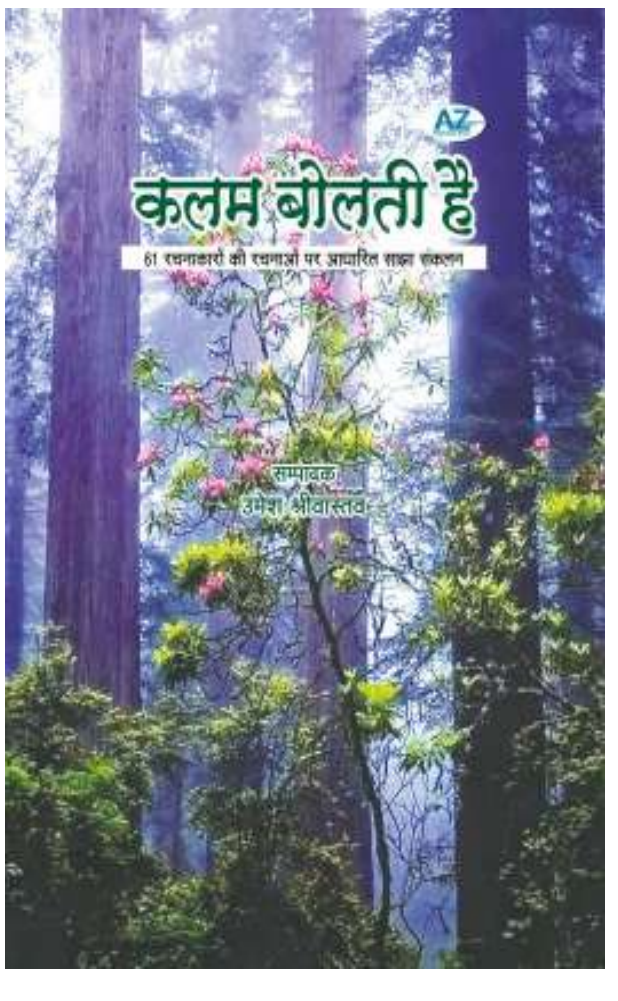


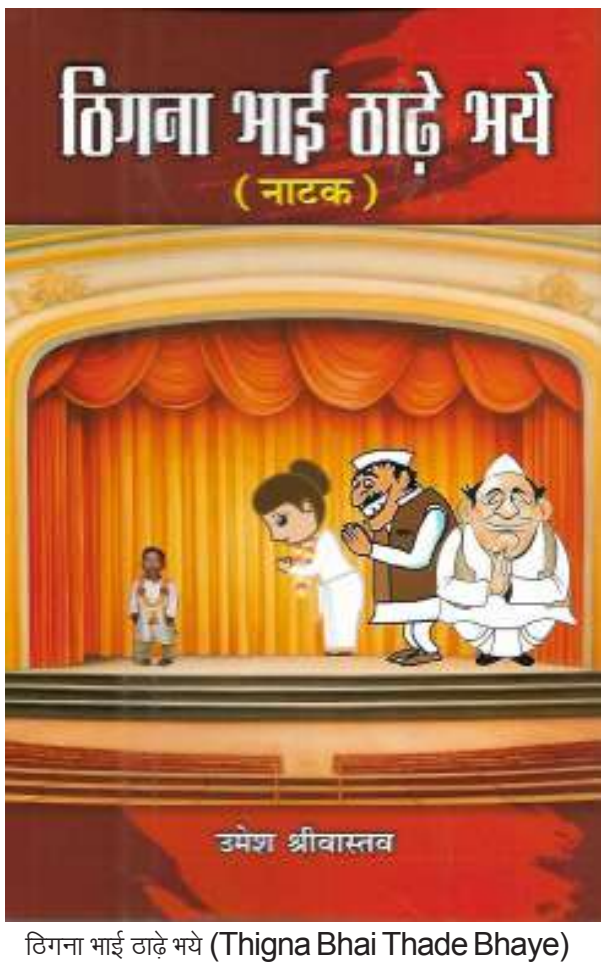
चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित





समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।





ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

ट्रंप की मुश्किलों का फायदा उठाएंगे जिनपिंग! ताइवान पर होगा चीन का कब्जा, समुंदर में उतर गए 100 युद्धपोत



एक बार फिर से अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ गए हैं। कारण स्पष्ट है एनवीडिया जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के एक बार चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। दरअसल एनवीडिया को लेकर बढ़ते विवाद के बीच चीन ने अमेरिका को सेमीकंडक्टर के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाने के खिलाफ चेतावनी दी है। चीन का कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध वैश्विक सप्लाई चेन को बाधित कर सकता है। चीन जो कह रहा है अगर इस पर अमल हो जाता है तो भारी नुकसान अमेरिका को सहना पड़ सकता है। बीजिंग ने चीन पर लगाए जा रहे जासूसी के आरोप से जुड़े कथित संबंधों को भी खारिज किया है। यानी कि जो एनवीडिया वाला विवाद था उस पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है और उसने सीधे–सीधे खारिज कर दिया है इस इन सभी आरोपों को। वहीं अमेरिका ने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों के बीच चीन को एडवांस एआई चिप के निर्यात पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो रही है। एनवीडिया वाले मामले के बाद भारी जो है कि चीन पर आरोप लगे हैं अमेरिका की तरफ से और यही कारण है कि इस मामले को लेकर के अब जो है कि धीरे–धीरे चीन और अमेरिका लड़ना शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात बीते दिन हुई थी। आने वाले दिनों में भी होने वाली है। दूसरी तरफ यह एनवीडिया का विवाद जो है यह टेंशन दोनों मुल्कों के बीच बढ़ा रहा है। खासतौर पर चीन के ऊपर आरोप लग रहे हैं। जासूसी के शक हमेशा से चीन के ऊपर रहता है।

दूसरी तरफ ताइवान का एंगल आ गया है। जिनपिंग ताइवान को विलय कराना चाहते हैं चीन के अंदर। चीन की सेना समंदर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़ी है। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है। मामला यह है कि अमेरिका से लेकर ताइवान तक चिंता बढ़ चुकी है। इस बात के बाद 100 से ज्यादा चीनी युद्धपोत और कोस्टगार्ड जहाज, तीन सैन्य कमांड की एक साथ सक्रियता और ताइवान के शहरों को निशाना बनाने की मॉक ड्रिल हुई है। अब सवाल यह है कि क्या चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है या फिर अमेरिका को चुनौती देने और ताइवान पर दबाव बनाने की रणनीति यह अपने आप में बड़ा सवाल है। चीन लगातार ताइवान को लेकर के बहुत ही चिंतित है और वो नहीं चाहता है कि अमेरिका का कोई भी उस पर हस्तक्षेप हो। अमेरिका हालांकि कमजोर हो पड़ चुका है क्योंकि जिस तरीके से मिड टर्म चुनाव है मिड टर्म चुनाव के बाद अमेरिका जो है कि अपने मामले को लेकर के बड़ा उलझा हुआ है। ईरान युद्ध, दूसरा रूस यूक्रेन संघर्ष और घरेलू राजनीति के बीच डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीन की चुनौती भी खड़ी है। चारों तरफ से अमेरिका घिर चुका है और यही कारण है कि ऐसे में सी जिनपिंग एक मौका या फिर फायदा उठाना चाहते हैं इस मामले को लेकर के क्योंकि उनको भी पता हो गया है कि अभी जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनकी ताकतें कम हो चुकी हैं। दोनों सदन हार चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप तो विपक्ष और पक्ष जो है वहां पर दोनों की शक्तियां का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनपिंग को एक बड़ा मौका मिला है और यही कारण है कि खुलकर के चेतावनी भी दे रहे हैं। चीन में पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि अभी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। 12 नवंबर को जिनपिंग ने ताइवान के पूर्ण एकीकरण को इतिहास का अटल लक्ष्य बताया। मतलब उन्होंने कहा कि हम इसको शामिल करके ही रहेंगे। उन्होंने कहा था कि चीन शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान का विलय चाहता है। ठीक है लेकिन जिनपिंग के बयान के अगले दिन ये रिपोर्ट आती है कि यहां पर बड़ा एक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है और टारगेट ताइवान को कैसे किया जाए? इसके लिए बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू हो गया।

भारत का नाम लेकर ऐसा चिल्लाया यूरोपीय नेता, सब ने किया सरेंडर!

यूरोप की संसद में अचानक कुछ ऐसा हुआ जो देखने लायक है, यूरोपीय संसद में ऊपर बैठे एक सांसद ने चिल्लाकर भारत का नाम लिया, उसके बाद चीन का नाम लिए और आखिर में सबने सरेंडर कर दिया। दरअसल यूरोपीय संसद में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों से किसे फायदा हो रहा है और क्या यह यूरोप के लिए सही रणनीति है। बहस के दौरान ऊपर बैठे एक सांसद ने पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे जर्मन यूरोपीय संसद सदस्य (डम्ब्) माइकल गाहलर से चिलाकर कहा कि रूस पर प्रतिबंधों के कारण सस्ता तेल और गैस भारत और चीन को मिल रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि इससे यूरोपीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है और भारत व चीन को फायदा पहुंच रहा है, जवाब में माइकल गाहलर ने कहा कि वे भारत और चीन की इस स्थिति से खुश नहीं हैं, लेकिन यूरोप इसे रोक नहीं सकता, हम भारत या चीन से यह मांग नहीं कर सकते कि वे क्या करें और क्या न करें। संसद में एक सदस्य ने यूरोपीय संघ (म्) की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतिबंधों का असली फायदा भारत और चीन को मिल रहा है। उन्होंने कहा, ष्आपने पूछा कि इन प्रतिबंधों से किसे फायदा हो रहा है? इसका जवाब भारत और चीन हैं, क्योंकि मध्य यूरोपीय देशों को मिलने वाला सारा सस्ता तेल और गैस अब वहां जा रहा है। क्या यूरोपीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाना और भारतीयों व चीनियों को फायदा देना उचित है? इससे हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिबंधों के बिना की स्थिति से भी बदतर हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि यूरोप के लिए यह सही रणनीति है हम भारत और चीन को निर्देश नहीं दे सकतेश्इस सवाल के जवाब में दूसरे वक्ता ने वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से पैदा हुई तेल की कमी का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप संप्रभु देशों की व्यापार नीतियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। उन्होंने कहा हम भारत या चीन से यह मांग नहीं कर सकते कि वे क्या करें और क्या न करें। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने के कारण वर्तमान में हम तेल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और यही वजह है कि हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से जहां से भी संभव हो, तेल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन की इस स्थिति से मैं खुश नहीं हूं, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। हालांकि, हमें खुद रूस की आय में कोई योगदान नहीं देना चाहिए।ष्यह चर्चा ऐसे समय में सामने आई है जब होर्मुज संकट और रूस–यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित है और यूरोपीय देश अपने उद्योगों को बचाने तथा रूस की आर्थिक घेराबंदी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रहे हैं।

रूस के साथ इन देशों ने भरा भारत का तेल खजाना, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में उलझे रहे और इधर हो गया खेल



दुनिया इस वक्त ऊर्जा संकट और युद्ध के भंवर में फंसी हुई है। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते को जोखिम से भरा हुआ देखा जा रहा है। लेकिन इस वैश्विक उथल–पुथल के बीच भी भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि 140 करोड़ की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा कैसे तय की जाती है। हाल ही में दो बेहद अहम आंकड़े सामने आए जो भारत की ऑयल डायवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी की पूरी तस्वीर को बयां करते हैं। पहला आंकड़ा आया है स्वतंत्र रिसर्च संस्थान क्रिया की रिपोर्ट से जिसके मुताबिक अक्टूबर 2026 में भारत ने रूस से रिकॉर्ड 6. 4 बिलियन यूरो यानी कि लगभग 58000 करोड़ का हाइड्रोकार्बन और कच्चा तेल खरीदा है। यह जनवरी 2022 के बाद से भारत का किसी एक महीने में रूस से किया गया सबसे बड़ा आयात है। लेकिन ठीक इसके बाद नवंबर के महीने में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। यह जो आंकड़ा है यह आया है ब्लूमबर्ग और केप्लर के डाटा के अनुसार। नवंबर के महीने में भारत ने रूस को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर पर्शियन गल्फ यानी कि खाड़ी देशों से ज्यादा कच्चा तेल मंगवाना शुरू कर दिया। नवंबर में खाड़ी देशों से करीब 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल भारत पहुंचा है। जबकि रूस से ये आंकड़ा 1.8 मिलियन बैरल पर डे रहा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। सीआरईए क्रैक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में भारत रूस से जीवाश्म ईंधन खरीदने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा खरीदार बना। चीन 10.7 बिलियन यूरो के साथ पहले नंबर पर था। जबकि भारत 6.4 बिलियन यूरो के साथ दूसरे स्थान पर। इस खरीद की बारीकियों को अगर हम समझे तो भारत की इस 6. 4 बिलियन यूरो की जो कुल खरीद थी उसमें 91: हिस्सा कच्चा तेल क्रूड ऑयल था। जिसकी कीमत करीब 5.8 बिलियन यूरो थी। बाकी ऐसे में 333 मिलियन यूरो का कोयला और 232 मिलियन यूरो के पेट्रोलियम उत्पाद शामिल थे। भारत की तीन सबसे बड़ी रिफाइनरियों ने अपनी खरीद में भारी बढ़ोतरी की। द एनर्जी की वार्डनार रिफाइनरी में 12: की बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल की पारादीप में 28: की और त्मसपंदबम प्दकनेजतपमे की जामनगर रिफाइनरी में तकरीबन 22: का उछाल देखा गया। इसके साथ ही जामनगर रिफाइनरी दुनिया में समुद्र के रास्ते से रूसी तेल मंगाने वाली सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि पश्चिमी देश जो भारत पर सवाल उठाते हैं, वह खुद भारत की इन्हीं रिफाइनरियों से प्रोसेस किया हुआ तेल खरीद रहे हैं। अक्टूबर में भारत, तुर्की और बर्नेई की रिफाइनरियों से करीब 1.6 बिलियन यूरो के तेल उत्पाद यूरोप यूनियन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भेजे गए हैं। आप समझिए कि अक्टूबर में रूस से इतनी बड़ी खरीद की नौबत आखिर क्यों आई? दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हुए सैन्य तनाव के कारण जो अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति का सबसे संवेदनशील रास्ता है स्टेट ऑफ हार्मोस वो लगभग ठप सा पड़ गया। युद्ध से पहले भारत इस रास्ते से रोज 2.8 बिलियन बैरल कच्चा तेल मंगाता था। लेकिन जब युद्ध चरम पर पहुंचा और जहाजों पर हमले बढ़ते हुए दिखाई दिए तो अप्रैल के महीने में यह आपूर्ति घटकर महज 247,000 बैरल प्रतिदिन रह गई थी। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोस से तेल का निकलना मुश्किल हुआ। तो वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल का दाम अचानक बढ़ गया। भारत के पास अपनी रिफाइनरियों को चालू बनाए रखने और देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत ना होने देने के लिए रूस ही सबसे बड़ा सहारा बना। भारत ने अपनी रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए रूस से बड़ी मात्रा में तेल उठाया और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया और उसे सुरक्षित किया। लेकिन असली डिप्लोमेसी और बिजनेस प्रोड्यूस यानी कि व्यापारिक सूझबूझ तब सामने आती है जब हालात बदलते हैं। जैसे ही नवंबर का महीना शुरू हुआ, भारत ने गल्फ देशों की तरफ अपना रुख तेज कर दिया। और अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे तीन बड़े आर्थिक और सामरिक कारण है। पहला कारण है शिप टू शिप ट्रांसफर और हॉर्मोस की बहाली। शेट ऑफ हॉर्मोस में सीधे जान के खतरे को भांपते हुए खाड़ी के तेल उत्पादक देशों ने एक नया रास्ता निकाला है। उन्होंने ओमान की खाड़ी और भारत के पश्चिमी तट के करीब समुद्र में जहाजों से जहाजों में तेल ट्रांसफर एसटीएस ऑपरेशंस करना शुरू कर दिया। यहां तक कि भारत की कच्छ की खाड़ी गल्फ देशों के लिए तेल का एक सुरक्षित ट्रांसपोर्ट पॉइंट बन गया। इससे खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई लाइन फिर से बहाल हो सकी है। दूसरा कारण है दूरी और फ्रेट कॉस्ट यानी कि माल ढुलाई का जो खर्च रूस से भारत तेल लाने में हफ्तों का समय लगता है। जहाजों का बीमा महंगा है और फ्रेट कॉस्ट बहुत ज्यादा बैठ जाती है।



वहीं के वहीं खड़े हो गए 13 हजार प्लेन, अमेरिका में क्यों मच गया कोहराम, बड़ी आतंकी साजिश?

अमेरिका में हवाई उड़ानों पर लगी रोक हट गई है। फेडरल एिएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफएए ने रोक हटा दी है। पूरे अमेरिका में उड़ानों पर रोक लगी थी। फिलहाल ये रोक हटा दी गई है। अमेरिका के सभी एयरपोर्ट पर विमान ग्राउंडेड हुए थे। फ्लाइट्स के ग्राउंडेड होने की वजह से विमान के रुकने की वजह से इस रोक की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई फ्लाइट्स रद्द हो गई थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। अमेरिका में करीब 13,000 विमानों के उड़ने पर रोक लगी थी। सुरक्षा कारणों से उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। फेडरल एिएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह रोक लगाई गई थी। 22 एटीसी सेंटर्स में कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया था। पूरी तरह से ठप हो गया था। कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही थी। जिस वजह से यह फैसला लिया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने की अब जांच चल रही है कि ऐसा क्यों हुआ। इस बीच 9/11 हमले के बाद पहली बार उड़ाने रुकी थी। 2023 में दूसरी बार फ्लाइट की उड़ानों पर रोक लगी थी। विमान रद्द होने पर अमेरिका के गृह मंत्री मार्क विन मुलन ने बयान दिया यह कोई दूसरा 9/11 नहीं है। डरने की बात नहीं है। सवाल उठ रहे थे कि क्या साइबर अटैक का मामला तो नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और डरने वाली बात नहीं है।

क्या साइबर अटैक था?

इतनी बड़ी तादाद में और इस प्रकार का ब्रेकाउन होना वो भी एक सुपर पावर के पूरे एयर मैनेजमेंट सिस्टम में एक अद्भुत वाकया है। सिस्टम फेलियर था या कोई टेररिस्ट अटैक का अंदेशा होने के कारण इन फ्लाइट्स को ग्राउंडेड किया गया। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इतना डस्टिंग एक्शन लेना कि सारी फ्लाइट को तुरंत ग्राउंड के ऊपर उतार दिया जाए। ये कोई छोटा–मोटा वाक्य नहीं है। अमेरिकी परिवहन मंत्री ने किसी भी साजिश से इंकार नहीं। अमेरिकी मंत्री ने कहा उड़ान सेवाओं में साजिश हो सकती है। अगर एयरलाइन ऑपरेशंस के बारे में जानकारी रखते हो एक बार जब आपने शेड्यूल्ड फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया। उसके बाद में उनको रिशेड्यूलिंग करना, एयर स्पेस मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। जिसके अंदर कौन सी रूट से कौन सी हाइट के ऊपर कौन सी फ्लाइट कौन सी दिशा को जाएगी। एक दूसरे के अंदर जहाज हवा हवा के अंदर ही उनका एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक बार जब सिस्टम फेलियर होता है।

हाफिज सईद समर्थित PMML ने मरियम नवाज को भेजा लीगल नोटिस, सात दिनों में माफी मांगने की मांग

लाहौर। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़े पाकिस्तान के एक राजनीतिक दल ने पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को एक कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनके उन बयानों को लेकर दिया गया है, जिनमें उन्होंने इस दल को "आतंकवादी", "गैर–कानूनी" और "प्रतिबंधित" संगठन बताया था। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) पार्टी ने शुक्रवार को मांग की कि मरियम नवाज अपनी टिप्पणी वापस लें, सोशल मीडिया से विवादित सामग्री हटाएं और सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगें। पीएमएमएल को व्यापक रूप से जमात–उद–दावा (जेयूडी) का राजनीतिक मोर्चा माना जाता है। जेयूडी की स्थापना हाफिज सईद ने की थी, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है और पाकिस्तान में उसे आतंकी वित्त पोषण के कई मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक विवाद आठ नवंबर को गुजरांवाला नेशनल असेंबली निर्वाचन क्षेत्र (एनए–77) में हुए उपचुनाव के बाद शुरू हुआ, जहां नवाज शरीफ की सत्ताधारी पार्टी 'पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज' (पीएमएल–एन) ने अपनी सीट बरकरार रखी। इस सीट से उनके उम्मीदवार राशिद बशीर विर्क को 43,365 वोट मिले, जबकि पीएमएमएल के उम्मीदवार इब्राहिम गुज्जर को 30,218 वोट प्राप्त हुए। पीएमएमएल ने नतीजों को खारिज कर दिया, धांधली का आरोप लगाया और दावा किया कि उसका उम्मीदवार जीता है। उसने 50 मतदान केंद्रों पर दोबारा गिनती की मांग की। पंजाब की सूचना मंत्री अजमा बुखारी ने सवाल उठाया था कि राज्य द्वारा प्रतिबंधित घोषित किए गए संगठन कैसे अपने नाम बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं। मरियम नवाज ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिबंधित संगठनों और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ' ने नए नामों से पीएमएल–एन के खिलाफ उपचुनाव लड़ा था।

UK Court ने भारतीय छात्र Bilal Qazi को बाल यौन शोषण में सुनाई 30 साल जेल

लंदन। ब्रिटेन में 27 वर्षीय भारतीय छात्र को उत्तर–पश्चिम इंग्लैंड में कई बच्चों का ऑनलाइन शोषण करने और उन्हें यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करने के जुर्म में शुक्रवार को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गयी। ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे ऐसा व्यक्ति बताया है जो लगातार ऑनलाइन माध्यमों से बच्चों या किशोरों को अपने विश्वास में लेकर उन्हें यौन शोषण के जाल में फंसाता है। बिलाल काजी को ऑनलाइन बाल यौन शोषण के कई अपराधों का दोष स्वीकार करने के बाद चेस्टर क्राउन अदालत में सजा सुनाई गई। अदालत में बताया गया कि काजी ने 10 से 15 साल की उम्र की लड़कियों का विश्वास जीतने के लिए सोशल मीडिया और गेमिंग मंच पर एक किशोर होने का नाटक किया था।

पेनपा त्सेरिंग का आरोप, तिब्बत में वर्चस्ववादी मॉडल पूरी दुनिया पर थोपना चाहता है चीन

वाशिंगटन। तिब्बत के निर्वासित सरकार के नेता सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने कहा कि तिब्बत में चीन की वर्चस्ववादी हरकतें इस बात का एक नमूना हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ आगे क्या करने की योजना बना रहा है। त्सेरिंग इस समय अमेरिका में हैं जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों और कांग्रेस सदस्यों से मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिकी कांग्रेस के नेता 'अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट' (एएफटीए), 2026 पर विचार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को तिब्बती लोगों की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के रूप में मान्यता दिलाना है। अमेरिकी नेतृत्व के साथ अपनी मुलाकातों के दौरान त्सेरिंग ने तिब्बती पहचान को मिटाने की चीन की कोशिशों पर चिंता जताई जिसे उन्होंने ''सांस्कृतिक नरसंहार'' का नाम दिया। त्सेरिंग ने यहां 'पीटीआई–भाषा' से कहा, ''मैं हमेशा यही कहता हूं कि चीन तिब्बत में जो कर रहा है, वह एक तरह का मॉडल है जिसे वह पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी पर थोपना चाहता है। चीन का वर्चस्ववादी रवैया 1950 में तिब्बत से शुरू हुआ था। अब यह पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर तक फैल रहा है।'' तिब्बती नेता ने भारत के साथ चीन के सीमा विवाद, दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जापान के प्रति उसके आक्रामक रुख का जिक्र करते हुए कहा कि बीजिंग इन मुद्दों के जरिये अपने लिए ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वह अपने फायदे के लिए कर सके। त्सेरिंग ने कहा, ''चीन अपने फायदे के लिए ऐसी स्थितियां बनाने में बहुत माहिर है। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसे वह सुलझाना नहीं चाहता तो वह उसे कभी नहीं सुलझाता।'' त्सेरिंग ने दावा किया कि चीन दुनिया के सामने अपनी 'शांतिपूर्ण प्रगति' का झूठा विमर्श पेश कर रहा है। ऐसा करते हुए वह जापान, ताइवान, फिलीपीन और दक्षिण–पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को पूरी तरह छिपा जाता है। उन्होंने कहा कि तिब्बत के भीतर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और तिब्बती लोग धीरे–धीरे मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। त्सेरिंग ने कहा कि तिब्बती भाषा में लिखे गए संकेतक बोर्ड पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मठों के डिजाइन में बदलाव किए जा रहे हैं और तिब्बतियों पर चीनी संस्कृति थोपी जा रही है। त्सेरिंग ने कहा, ''यह ऐसा है जैसे कोई अजगर नहीं बल्कि 'ड्रैगन' धीरे–धीरे लेकिन बड़ी मजबूती से आपको जकड़ रहा हो। इसलिए, इसे एक तरह का नरसंहार, या कम से कम सांस्कृतिक नरसंहार कहा जा सकता है।'' तिब्बती नेता ने कहा कि तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों पर दुनिया खामोश है और अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रही है।



प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़

संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक (तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईएन/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।